THE VICE-CH/ IRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA); Now, we go to the Private Members' Legislative business.

SHRI JAGDISH P IAS AD MATHUR (Uttar Pradesh); Sr...

THE VICE-CHA IRMAN (SHRI SAWAISINGH SIS(DIA): No more clarifications, pleac<. You have not given your name.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: I will ask just one thing. He made the statement just now only.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): It becomes difficult to go to the next item. All right, you go on.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मंहगाई काफी बढ़ गई है और पीछे जायेगी नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछला जो मंहगाई भत्ता है तो क्या इसको सेलरी में मर्जर करने पर सरकार विचार करेगी ?

SHRI MAGANBHAI BAROT: Will the hon. Member repeat the question?

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR; As the prici rise has been continuous, would ie consider the merger of DA into the basic salary of the employees?

SHRI MAGANBHAI BAROT: Sir, that is a question of policy. I am", at the moment, making a statement of fact only, namely, that particular average index having been reached, the standard that we have fixed is being made applicab e and we have given the allowance.

THE KERALA HIGH COURT (ESTABLISHMENT OF A PERMANENT BENCH AT TRIVANDRUM) BILL, 1980

SHRI S. KUMARAN (Kerala): Sir, I beg to move for ltave to introduce a Bill to provide f< r the establishment °f a permanent bench of the High Court of Kerala at Trivandrum.

The question was put and the motion was odopted.

SHRI S. KUMARAN: Sir, I introduce the Bill.

THE CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL1980 (AMENDMENT OF SECTION 3)

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY (West Bengal): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Citizenship Act, 1955.

The question was put and the motion was adopted.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: Sir, I introduce the Bill.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1977 (TO AMEND THE SECOND SCHEDULE)—contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): We will now take up further consideration of the Constitution (Amendment) Bill, 1977, moved by Shri Bhupesh Gupta.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Sir, I may remind the hon. Members that the Bill relates t_0 the reduction of President's salary to Rs. 5,000 and that of the Governors' to Rs. 3,000. This is the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): Yes, Shri Hukmdeo Narayan Yadav.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक सदन में विचार के लिए आया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन को कितना रखा जाए, दो हजार, ढाई हजार या तीन हजार, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इसमें एक सिद्धान्त का सवाल पैदा होता है। मैं नहीं जानता कि वरिष्ठ

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

सदस्य माननीय भूपेश गुप्त जी, जो इस विधेयक को सदन में रखा है वे इस पर विभाजन करायेंगे या इस बिल को वापिस ले लेंगे यह मैं नही जानता लेकिन केवल बहस तक के लिए अगर उन्होंने यह विधेयक लाया है तो केवल बहस तक ही नहीं रहना चाहिए बल्कि इस विधेयक की मार्फत दो विचारधारायें जो हिन्दुस्तान में हैं उनका भी प्रतिपादन इसी सदन में होना चाहिए । एक विचारधारा देश के अन्दर यह है कि देश के सर्वोच्च वर्ग के जो कुछ लोग हैं या देश के अन्दर मुट्ठी भर जो सुविधा भोगी लोग हैं उनके लिए क्या और सुविधाएं बढ़ाई जाएं या उनकी सुविधाओं को काटने का काम किया जाए । एक तरफ हिन्दुस्तान के अन्दर न केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल बल्कि एक प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो सुविधाभोगी क्लास में आते हैं उनके ऊपर हिन्दुस्तान की आमदनी का लगभग 95–96 प्रतिशत खर्च हो जाता है और फिर देश के अन्दर जो गांव में बसने वाले 85 प्रतिशत लोग हैं या खेती में लगे हुए 70 प्रतिशत किसान हैं उनके प्रति इस देश में कुछ भी सोचने का काम नहीं होता । राष्ट्रपति और राज्यपाल जो होते हैं वे संविधान के अनुसार राष्ट्रपति देश के प्रतीक माने जाते हैं और राज्यपाल प्रान्त के प्रतीक माने जाते हैं । राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर जो खर्च हिन्दुस्तान में होता है अगर अमरीका के राष्ट्रपति और हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति नों के खर्च की तुलना की जाए तो पता लगेगा कि यह हिन्दुस्तान गरीब देश होते हुए भी कितना ज्यादा मन से सामंतवादी देश है । अमरीका के अन्दर लोगों की जो वार्षिक आय है वह हिन्दुस्तान के लोगों की वार्षिक आय की बनिस्बत कई गुना अधिक है । यह कहा जाये तो यह एवरेस्ट की चोटी और पाताल के बराबर दोनों के बीच में असमानता है । जहां अमरीका के अंदर लोगों की वार्षिक प्रति व्यक्ति सालाना आय इतनी ज्यादा है वहां के राष्ट्रपति चार एकड़ जमीन में बंगला बनाकर रहते हैं और हिन्दुस्तान में जहां प्रति व्यक्ति औसत आय सन् 77–78 के रुपये के मूल्य में सात सौ रुपये आती है वहां के राष्ट्रपति के रहने का कुल रकबा 6 सौ एकड़ होता है । अमरीका में जहां प्रति व्यक्ति जो लोगों की औसत जमीन है, जोतने की जमीन है और हिन्दुस्तान में प्रति व्यक्ति औसत जोत की जो जमीन है इन दोनों के बीच में भी इतना ही बड़ा अंतर है । हिन्दुस्तान में जहां 0.32 एकड़ जमीन प्रति व्यक्ति पड़ती है वहां अमरीका के अंदर कहां चार एकड़ से भी कुछ ज्यादा जमीन पड़ती होगी । फिर दोनों के बीच में यह तुलना करें ।

हर राज्यों में राज्यपालों के जो मकान बने हुए हैं उन राजधानियों में राज्यपालों के मकानों को जाकर देखें कि कितनी जमीनों में उनके मकान बने हुए हैं । न केवल राष्ट्रपति के भवन को ही देखें बल्कि दिल्ली के अंदर चले जायें तो जो मंत्रियों के रहने के बंगले हैं, संसद् सदस्यों के रहने के बंगले हैं उन बंगलों में एक एक दो-दो एकड़ जमीन फिजूल पड़ी हुई है । जिस पर खेती नहीं होती है और दूसरी तरफ हिन्दुस्तान के गांवों में खेती करने वाले किसान जो जमीन को जोतकर पैदा कर सकते हैं जिनके हाथ जमीन को जोतने के लायक हैं उनके पास जोतने के लिए जमीन नहीं है । एक तरफ हिन्दुस्तान में जोतने के लिए जमीन नहीं है कि वे पेट भर सकें या अपने परिवार का गुजारा कर सकें और दूसरी तरफ हिन्दुस्तान में एक सुविधा भोगी क्लास है जिसके बंगले और अहाते में सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है, जिसमें खेती नहीं होती है, उत्पादन नहीं होता है । इसके अंदर

यह सवाल भी पैदा होता है कि केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन का सवाल नहीं है, संसद् और विधान मंडलों में रहने वाले लोगों की सुविधा का सवाल नहीं है बल्कि सवाल यह पैदा होता है कि इस देश के अंदर जो 85 प्रतिशत आदमी गांवों में रहने वाले हैं उनमें और उनके ऊपर जो शासन चलाने वाले लोग हैं उनकी आमदनी के अंतर का कोई रेखांकन होगा या नहीं । उनकी क्या आमदनी होगी । फिर आज उनके ऊपर शासन चलाने वाले जो लोग हैं, सत्ता में रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच में आमदनी का क्या फर्क पड़ेगा ।

हिन्दुस्तान में औसत आमदनी निकालने का नकली तरीका है वह जो मेरे जैसे गांव में बसने वाले लोग हैं उनकी आंखों में धूल झोंकने के सिवाय कुछ नहीं है। राष्ट्रपति के ऊपर 10 हजार रुपया महीना खर्चा और गांव में एक हाई स्कूल मास्टर या प्राईमरी स्कूल मास्टर अथवा बिहार के अन्दर चपरासी का कार्य करने वाले का वेतन डेढ़ सौ या दो सौ रुपये है । अब औसत आमदनी निकालो । 10 हजार पर दो सौ जोड़कर इसका आधा पड़ गया 5100 रुपया । क्या यह औसत आमदनी है । नदी में पानी का औसत निकालो, कहीं 50 फुट कहीं पांच और कहीं दस फुट नापकर औसत निकालो । गंगा जी में रह जाओ और डूबकर सर्वनाश हो जाओ । तो क्या इस तरह से हिन्दुस्तान में औसत आमदनी निकलने का तरीका है, यह मैं पूछूंगा ।

अमरीका में औसत आमदनी और न्यूनतम आमदनी इन दोनों को क्या कभी आपने निकालने को सोचा है? अमरीका में जो न्यूनतम प्रति व्यक्ति आमदनी है और सालाना प्रति व्यक्ति जो औसत आय है इन दोनों के बीच में कोई एक और सवा का ही अंतर आता है । अगर न्यूनतम आमदनी एक रुपये प्रति व्यक्ति है तो औसत आमदनी सवा या डेढ़ रुपये प्रति व्यक्ति होगी । हिन्दुस्तान में अगर एक तरफ औसत आमदनी सात सौ रुपये पड़ती है तो हिन्दुस्तान में गांव में बसने वाले सौ में से 60 आदमी होंगे जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं अर्थात् 15 रुपये माह, आठ आने प्रति दिन पर गुजारा कर रहे हैं । इस दिल्ली, पटना, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे शहरों के अंदर जहां आलीशान महलों के अंदर रात दिन ऐशों आराम की जिन्दगी व्यतीत करने वाले थोड़े से लोग हैं वहां इन्ही शहरों के अन्दर 41 फीसदी लोग गरीबी की रेखा से नीचे बसकर अपना गुजारा कर रहे हैं । इस दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में चले जाइये, जमुना पार के इलाके में चले जाइये, उन झोंपड़ियों में चले जाइये जहां लोगों को पीने का पानी नहीं है, गरीबों के लिए पाखाने का इंतजाम नहीं है और फिर दूसरी तरफ इस देश के अंदर हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति और राज्यपालों पर इतना पैसा खर्च करने का हिन्दुस्तान के लोगों को क्या नैतिक अधिकार है, मैं यह जानना चाहता हूं । जहां पर कि हिन्दुस्तान के गांवों में बसने वाली मां-बहनों के लिए इस आजाद भारत में पाखाने का इंतजाम नहीं है । आज गांव के अंदर सूर्यास्त के वक्त हमारे घर की बहनें पाखाने के लिए सड़क के किनारे बैठती हैं और जब रास्ते से कोई मुसाफिर चलता है तो आधा पाखाना पेट में लिए हुए लाज के मारे सड़क पर खड़ी हो जाती हैं । आखिर आज देश में गांवों में रहने वाली करोड़ों मां और बहनों के लिए पाखाने का इंतजाम जरूरी है कि इस देश के अंदर मुट्ठी भर लोगों के ऊपर इतना पैसा खर्च करने की आवश्यकता है ।

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

यह सवाल इस दृष्टिकोण का है कि उसमें पैसा जो राष्ट्र का है, राष्ट्र के संचित निधि का पैसा खर्च करेंगे वह संचित कोष का पैसा खर्चा किधर होगा, किधर खर्चा करना चाहते हैं।

इसलिए, उपसभाध्यक्ष जी, राज्यपाल का जो वेतन है वह जो कुछ भी हो, लेकिन वेतन के साथ-साथ उनकी सुविधा के ऊपर जो खर्च होता है वह बेशुमार होता है। गांव में कहावत है—एक पैसे की मुर्गी और नौ पैसे का मसाला। तन्ख्वाहें तो हैं दो हजार, तीन हजार, पांच हजार, उसमें जो मसाला ऊपर का है, सुविधा, सवारी, अलटन-पलटन, लाव-लश्कर यह जो चारों तरफ हैं, उसके ऊपर जो खर्चे होते हैं कभी हिन्दुस्तान की संसद् में हिन्दुस्तान के एक महापुरुष ने आंकड़ों से यह सिद्ध किया था कि प्रधान मंत्री पर पच्चीस हजार रुपया खर्च होता है। वे महापुरुष थे डा० राम मनोहर लोहिया जिसने सिद्ध किया था कि प्रधान मंत्री पर प्रतिदिन पच्चीस हजार रुपया खर्च होता है। यह आंकड़े 1951, 1952, 1953 और 1954 के हैं और आज के रुपये के मूल्यांकन से तो कुछ ज्यादा ही आएगा।

फिर हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री के ऊपर हर रोज जोड़ा जाए, केवल उनके दरमाहा में नहीं, उनके जो भाषण होते हैं, एक एक भाषण पर जो खर्चा होता है—मैं बिहार का रहने वाला हूं, बिहार विधान सभा में भी 11 साल अपनी जिंदगी को मैंने गुजारा है। हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी जब विधान सभा के चुनाव के लिए बिहार के दौरे पर गई थीं, केवल एक रात के ठहरने के लिए सर्किट हाउस में, सर्किट हाउस के बाथ रूम को प्रधान मंत्री के लायक बनाने के लिए 45,000 रु० खर्च किया गया था जो सर्किट हाउस के अन्दर बाथरूम को परिवर्तित करने के लिए खर्च किया गया क्योंकि प्रधान मंत्री के लायक वह बाथरूम नहीं था। अब देश के प्रधान मंत्री के लायक बाथरूम कुछ और होगा और हमारे जैसे साधारण लोगों के लिए बाथ रूम कुछ और होगा क्योंकि आदमी-आदमी के लिए बाथरूम भी बदल जाया करता है, प्रक्रिया भी बदलती है। इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि देश में एक महिला प्रधान मंत्री जो हैं उसके लिए आप एक रात के लिए बाथरूम पर 45,000 रुपया खर्च करने के लिए सही मान सकते हैं लेकिन देश में जो 80–85 तिशत महिलाएं जिनके लिए पाखाने का कोई इंतजाम नहीं है, उस पर नहीं सोचा जा सकता।

एक माननीय सदस्य : संडास कहो।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : संडास कहो या बाथ रूम कहो, भाई मैं गांव का रहने वाला हूं। यहां सब जगह लिखा है बाथरूम, चाहे उसमें पाखाना करो या स्नान करो।

श्रीमती नर्गिस दत्त (नाम निर्देशित) : बाथरूम से आगे बढ़िए ना।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : आगे तो मैं बढ़ रहा हूं, जरा सफाई कर दूं क्योंकि सफाई आने वाली है। इसलिए मैंने इन प्रश्नों को आपके सामने उठाया है कि जब सभा में खर्चे होते हैं, उनके आने जाने पर खर्चे होते हैं और मेरा दुर्भाग्य है—हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं, आधी धोती पहनते हैं और आधी तन पर रखते हैं। जिसके दिल में दर्द नहीं, वह दूसरे का दर्द क्या जाने, दुखिया का दुख क्या जाने।

जाके पर न फटे बेवाई
सो क्या जाने पीर पराई।

एयर-कंडिशनर और एयर कूलर लगाकर मकानों में रहने वाले लोग, गद्दे पर सोने वाले लोग और बड़ी-बड़ी फिल्मों में काम करने वाले लोग हमारी उस गरीबी को नहीं समझ पायेंगे । यह भी देखने का सवाल है, यह भी बुनियादी सवाल है कि जब कभी विदेशों के अन्दर ठाट-बाट, शान-शौकत, रंग-रलियों का सिनेमा दिखाया जायगा, तो बड़ी खुशी होती है । लेकिन हिंदुस्तान की गरीबी को कोई दिखला दे तो यहां के सिनेमा वालों के दिल में तकलीफ भी हो जाती है कि सच्चाई को ढक दो, सच्चाई को छिपा दो, सच्चाई पर पर्दा डालने का काम करो ।

उपसभाध्यक्ष जी, हम लोग नग्न सत्य जो समाज के सामने रखने के लिए राज्य सभा में आए हैं । मेरे लिए राज्य सभा राज्य सभा नहीं है । मेरे लिए राज्य सभा ग्राम सभा के रूप में जब परिवर्तित होगी, उस दिन कहीं भारत का सुधार हो सकता है । उस दिन कहीं भारत का कल्याण हो सकता है । मैं उनकी आवाज लेकर आया हूं जो गांवों में झोपड़ी के अन्दर रहने वाले हैं जिनको दोनों टाइम भोजन नहीं मिल पाता, जिनको आधा पेट रोटी नहीं मिल पाती । शहर में रहने वाले हमारे गांवों के गरीबों का दुख क्या जानें । मैं कहना चाहता हूं, यह देश जहां कभी एक ऐसा जमाना भी था जब हिन्दुस्तान के उस चम्पारन में महात्मा गांधी गए थे । गांधी जी जिस समय चम्पारन गए थे उस समय माता कस्तूरबा भी उनके साथ थी । गांव की गरीब औरतें सड़क के किनारे उस महात्मा को देखने आई थीं । उन गरीब औरतों को देख कर माता कस्तूरबा से गांधी जी ने कहा था कि ये औरतें धोती साफ क्यों नहीं करती ? माता कस्तूरबा हमारे चम्पारन की गलियों में गई और औरतों से पूछा, तो हमारी बहिनें कहने लगीं हमारे पास दूसरी धोती नहीं है फिर धोकर दूसरी पहनने का सवाल कहां से आता है । असंख्य मां-बहिनें ऐसी हैं जिनके पास धोती नहीं है तो आप उनके दुख को, उन गरीबन के दुख को नहीं जानोगे । हमारे बिहार में, दक्षिण में रहने वाली गरीब हरिजन और आदिवासी महिलाएं, माताएं रात में जब बच्चे रोते हैं तो अपनी कमर की साड़ी को खोल कर नंगी हो जाती हैं और उस साड़ी से अपने बच्चे के तन को ढक लेती हैं । शहर और गांव दोनों की संस्कृति और सभ्यता अलग हैं । गांव में पले लोगों और शहर के पले लोगों की संस्कृति और सभ्यता अलग हुआ करती है । आपका एसोसिएशन अलग हैं, हमारा एसोसिएशन अलग है । इसलिए दोनों की दिल की भावना अलग होगी । इनसान जिस मिट्टी में पैदा होता है उसकी संस्कृति उसी तरह की बनती है । इसलिए उपसभाध्यक्ष जी, बुनियादी प्रश्न यह है कि जो राष्ट्रपति या राज्यपाल के ऊपर इस देश में खर्च किया जा रहा है, वह पैसा कहां से आता है ? उस पैसे को देने वाले कौन हैं ? अप्रत्यक्ष कर हो या प्रत्यक्ष कर हो, हर तरह से, जो गांव के गरीब किसान हैं, वहीं ज्यादा देते हैं, क्योंकि खेती में लगे किसान ज्यादा हैं, 100 में 85 किसान हैं गांव में बसने वाले । इसलिए भारत सरकार की संचित निधि में जो पैसा आता है वह ज्यादातर किसान के पास से आता है, वह गांव वाला किसान देता है । लेकिन उस पैसे को खर्च करने का काम, उसके पैसे को बांटने का काम हिन्दुस्तान की सत्ता चलाने वाले और सरकार चलाने वाले लोग करते हैं । दुख होता है कि हिन्दुस्तान की सत्ता पर, हिन्दुस्तान की सत्ता के संचालन पर, हिन्दुस्तान की

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

1 नम्बर की कुर्सी पर जो लोग हैं उन पर उन गरीबों का अधिकार इस देश में नहीं हो रहा है। इसलिए उनकी आवाज नहीं गूंज रही है, उनकी बातें नहीं चल रही हैं। जो दूसरे लोग हैं, जो उन गरीबों का शोषण करने वाले लोग हैं, उनके पैसे पर देश के अन्दर आराम की जिंदगी बिताने वाले लोग हैं, हिन्दुस्तान की सत्ता उन्हीं के हाथों में चल रही है। इसलिए उपसभाध्यक्ष जी, श्री भूपेश गुप्त जी ने यह प्रश्न सदन के सामने लाया है। उन्होंने इस बात को रखा है कि राष्ट्रपति के ऊपर और राज्यपालों के ऊपर जो खर्चा होता है, तो हजार, दो हजार तीन हजार किसी आदमी को दरमाहा दे दीजिए लेकिन उस को दुनिया भर की सारी सुविधा भी दे दीजिए, तो काहे को वेतन और भत्ता। वेतन के साथ-साथ सुविधा का सवाल कहां गया? हमने कहा, मुर्गे के साथ मसाले को भी देखिए। मुर्गा तो कम है, गोश्त तो कम है लेकिन उसके साथ मसाला ज्यादा है। सुविधा उन को कई गुना ज्यादा मिलती है। इस हिन्दुस्तान के अन्दर जो अपने को गान्धी जी के रास्ते पर चलने वाले, गांधी जी का सपूत कहते हैं, और जिस ने गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने का वायदा किया था, जिसने कहा था हिन्दुस्तान उन लंगोट वाले गांधी का देश है मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, उस महात्मा ने कहा था कि आजाद हिन्दुस्तान में राष्ट्रपति किसी बड़े बंगले में नहीं रहेगा। उसी राष्ट्रपति भवन को देख कर किसी जमाने में गांधी जी ने कहा था कि हिन्दुस्तान के इस बड़े बंगले में जिसमें हिन्दुस्तान का बड़ा लाट रहता था, यह बहुत अच्छा होगा कि उस को अस्पताल में बदल दो। क्या गांधी जी की उस वाणी को भूल गए हो? गांधी जी को याद करो। अगर गांधी-वाद का नाम लेते हो तो गांधीवाद के अन्दर निर्गुण को सगुण रूप में बदलो, गांधीवाद के सगुण रूप पर देश के निर्माण का काम चलाओ। देश में गांधीवाद की 3 धाराएं चल रही हैं—सत्ताधीश गांधीवाद, मठाधीश गांधीवाद और कुजात गांधीवाद। एक गांधीवादी वह है जिसने सत्ता चलाने का काम किया है। एक गांधीवादी वह रहा है जो मठ में बैठ कर गांधी जी के दर्शन का विश्लेषण करने वाला रहा है। तीसरा गांधीवादी डा० लोहिया, श्री जयप्रकाश नारायण इत्यादि जो गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने वाला, जिंदगी बिताने वाला, जो गांधी जी के रास्ते पर चला है और जिस ने गांधी जी की नीति का विश्लेषण

3 P.M.

किया है। इसलिए सरकारी गांधीवादी मठाधीश गान्धीवादी को छोड़ कर संघर्ष वाले गांधीवादी का रास्ता हम लोगों ने अख्तियार किया था। इसलिए सवाल देश के सामने न केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल के भत्ते का है बल्कि देश के सामने सवाल पैदा होता है कि देश का भोग के रास्ते पर निर्माण होगा या देश के निर्माण के लिए त्याग के रास्ते पर चलना होगा। सवाल भोग और त्याग का है। भोग के रास्ते हिन्दुस्तान के निर्माण के काम को आगे बढ़ाया गया और 75 प्रतिशत लोगों को सुविधा न देने का काम किया गया।

अभी अभी आपने बोनस वगैरह का एलान किया । चारो तरफ जितने राजनैतिक दल के लोग हैं मैं उन से कहना चाहता हूं कि इन सरकारी कर्मचारियों के लिए और जो आर्गनाइज्ड, संगठित मजदूर हैं उन के वेतन और भत्ते को बढ़ाने का सवाल आएगा तो सभी राजनैतिक दलों के लोग उन की हां में हां मिलाने के लिए आगे आएंगे । कुल मिला कर लगभग 87 प्रकार के भत्ते इन संगठित मजदूरों को दिए जा रहे हैं । इन राज-कर्मचारियों को कुल मिलाकर 87 प्रकार के भत्ते दिए जा रहे हैं । फिर भी उन का पेट नहीं भर रहा है । हिन्दुस्तान की आमदनी का बहुत बड़ा अंश उन की सुविधा पर खर्च करते चले जाओ, लेकिन हिन्दुस्तान के गांव के उस किसान की ओर न देखो जो गांव में परिश्रम करता है, धरती को फाड़ कर दौलत पैदा करता है, जेठ की दोपहरी में, चिलमिलाती धूप में जब हम और आप एयरकंडीशन्ड कमरे में, ठंडे में आराम कर रहे होते हैं उस समय उसकी चमड़ी धूप में झुलस रही होती है । सावन-भादों की बरसात में जिस समय हम और आप आराम की जिन्दगी बिता रहे होते हैं उसके हाथ और पैर खेत में धान को रोपने में सड़ रहे होते हैं । जिस समय माघ की कड़ाके की सर्दी में आप अपने मकान को बिजली के होट से गर्म कर के सोते हो उस समय भोर में वह कड़ाके की सर्दी में गांव के अन्दर अपनी खेती को करने में मशगूल रहता है । जरा उन की तरफ देखो । सवाल न केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल की सुविधा का है, बल्कि इस के अन्दर सवाल छिपा हुआ है कि हिन्दुस्तान के अन्दर जो मुट्ठी भर निहित स्वार्थ का नया वर्ग बन गया है उस सुविधाभोगी वर्ग को तोड़ कर हिन्दुस्तान में ऐसा वातावरण बनाना है कि अन्त्योदय हो, जो लास्ट मेन है, उस समाज का सब से अन्तिम मानव है उस का कल्याण हो । गांधी जी ने कहा था कि अन्त्योदय हो । गांधी जी ने कहा था कि जब हिन्दुस्तान की सरकार बजट बनाए तो उस बजट में देखो कि उस में कितना पैसा समाज के अन्तिम मानव पर खर्च हो रहा है । अगर वहां जा रहा है तो बजट ठीक है । अगर उस में ज्यादा पैसा उन की ओर नहीं जा रहा है तो तुम्हारा यह बजट बेकार है । समाज का जो अन्तिम मानव है वह निर्माण के काम मे लगा हुआ है । उस की ओर देखने का काम करो, उसे बनाने का काम करो ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इन प्रश्नों का उत्तर मकवाणा साहब देंगे । मकवाणा साहब अभी हमारे दिल की बात को जानते नहीं लेकिन आज से दस-पन्द्रह साल पहले जब वे एम पी नहीं रहे होंगे वे मेरी इन बातों को अपनी आंख से देखते रहे होंगे । मकवाणा साहब ने न भी देखा हो, लेकिन जिस पीढ़ी से, जिस समुदाय से वे आए है उस समुदाय के लोग जिन बातों का मैं राज्य सभा में बखान कर रहा हूं उन को सदियों से भोगते रहे हैं, सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्षों से भोगते चले आए हैं । इसलिए मैं उन से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब कभी दब हुए समुदाय के लोग, शोषित वर्ग के लोग कुर्सी पर आओ तो अपने समुदाय के स्वार्थ को न भूल जाओ । यह हिन्दुस्तान का दुर्भाग्य है कि मुट्ठीभर आदमी जब कुर्सी पर रहते हैं तो वे अपने समूह के स्वार्थ का ख्याल रखते हैं । लेकिन जब हिन्दुस्तान का गांव का, किसान वर्ग का आदमी कुर्सी पर आता है तब वह अपने वर्ग स्वार्थ को भूल जाता है । उस का जो वर्ग चरित्र है उस को नष्ट कर दिया जाता है ।

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

कैसे ? किसी ज़माने की कहावत है । एक बार जब कहीं बहुत बड़ा कोप हुआ था, नागराज किसी आदमी पर बहुत गुस्से में आ गए और नागराज उस आदमी को डसने के लिए चले तो लोगों ने सोचा कि इस नागराज को वश में करने के लिए क्या उपाय किया जाय । कहीं थाली में दूध रख दिया गया, कहीं लावा रख दिया गया । दूध और लावे के जंगल में नागराज का गुस्सा ठंडा हो गया था । मकवाणा साहब, यहाँ राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, एम एल ए, एम पी के बंगले के चारों तरफ ठाट-बाट इसलिए किया जाता है कि जब कभी उन को सरकारी मुलाजिमों पर गुस्सा आवे और कार से उतर कर अपने बंगले में प्रवेश करें तो कहीं जुही, कहीं चमेली, कहीं गुलाब, कहीं नरगिस के (*Interruptions*) फूलों को देख कर उन का गुस्सा ठंडा हो जाय । उपसभापति महोदय, उन के बंगलों को सजाने का काम इसलिए किया जाता है कि उन फूलों की सुन्दरता से, उन फूलों की महक से, उन फूलों की बहार से उन का गुस्सा ठंडा हो जाय और अपनी असलियत को भूल जायें । याद रखिये हिन्दुस्तान के अन्दर, हिन्दुस्तान के प्राचीन इतिहास में भी कई बातें छिपी रहती हैं । एक बार इस देश में, हिन्दुस्तान की प्राचीन कथाओं के मुताबिक एक बार नहुष नाम का एक आदमी पैदा हुआ था जिस ने इंद्र लोक पर भी कब्जा कर लिया था । वह इन्द्र की गद्दी पर पहुंच गया था और उस ने इन्द्र की सत्ता पर कब्जा कर लिया था । लेकिन वह नहुष भी जब इन्द्र की कुर्सी पर बैठ गया तो वहाँ जा कर वह उसी ऐश आराम, ठाट बाट और शान शौकत में पड़ गया जिस में कि इन्द्र पड़ा हुआ था और नतीजा यह हुआ कि थोड़े दिन में ही उस नहुष को भी उस कुर्सी से हटा दिया गया । तो याद रखियें, हम और आप सब इस बात को याद रखें कि राष्ट्रपति और राज्यपालों पर जो खर्चा होता है वह बहुत ज्यादा है । और जगहों को तो मैंने नहीं देखा है लेकिन मैंने अपने बिहार के राज्यपाल के भवन को देखा है । जब मैं एक विधायक की हैसियत से उस राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में गया था तो उस समय उसे देखने का मुझे मौका मिला और उसे देख कर मेरे दिल में एक कचोट हुई थी । वहाँ गाय है, घोड़ा है, शेर है, उस के अन्दर देखने के लिये चिड़ियाघर है और उस के अन्दर जू बना हुआ है । उस के अन्दर क्या-क्या नहीं है । उस जमीन को घेर कर उन का मन बहलाने के लिये वह बनाया गया है । उन का मन बहलाने के लिये इतना खर्चा करने का आप को क्या अधिकार है ? क्यों इतना खर्चा उन पर हो रहा है ? यह नहीं किया जाना चाहिए । हिन्दुस्तान के अन्दर यह नियम बने, हिन्दुस्तान के अन्दर यह सवाल पैदा हो कि इतना खर्चा किसी के लिये नहीं किया जाना चाहिए और अगर आप ऐसा नहीं कर सके तो याद रखो कि आने वाले दिनों में गाँवों के अन्दर जो बेरोजगार नौजवान हैं, जो गंवई गाँव के गरीब किसान हैं, उन की जो झोपड़ियाँ हैं उन से एक आवाज निकल रही है, वहाँ से एक क्रांति की ज्वाला निकल रही है और वह दिल्ली की ओर बढ़ रही है । उस के दिल्ली तक पहुंचने के पहले आप लोग सावधान हो जाओ । इसके पहले कि वह ज्वाला इस भोग की नगरी को जला कर राख कर दे, इसके पहले कि इस नगरी के बसने वाले समाप्त हो जायें, मैं कहना चाहता हूं कि इस दिल्ली नगरी के रहने वाले सावधान हो जाएं । ऐ दिल्ली के रहने वालों, याद रखो कि दिल्ली एक ऐसी

प्रेमिका है जिस को सजाने के लिये इस के हर प्रेमी ने लाखों उपाय किये, लेकिन यह एक ऐसी प्रेमिका है कि जिसने अपने हर प्रेमी को लात मारने का काम किया है । हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली ने अपने प्रेमी को लात मार कर बिगाड़ने का काम किया है । दुनियां की किसी राजधानी के राजा इतनी अधिक संख्या में नहीं निकाले गये कहीं भी जितने कि दिल्ली में निकाले गए हैं । याद रखो, यह वही दिल्ली है जिस में कभी शान और शौकत के मद में आ कर औरंगजेब ने अपने भाइयों को हाथों में हथकड़ी लगा कर सड़कों पर टहलाने का काम किया था और इस दिल्ली में एक भी आवाज उस अन्याय के खिलाफ नहीं उठी थी । इस दिल्ली में उसके विरोध में एक भी आवाज नहीं उठी थी । दिल्ली में सुविधा भोगी लोग बसने वाले हैं । यह इस देश में एक नया वर्ग है । एक नम्बर का वर्ग है जो कुर्सी पर रहता है । अगर कुर्सी पाओ तो पाओ नहीं तो नम्बर दो वर्ग में आ जाओ तो अच्छा है । एक नम्बर का वर्ग तो कुर्सी पर अधिकार कर के रहता है लेकिन दिल्ली में बसने वाले अधिकतर लोग नम्बर दो वर्ग के हैं । अगर नम्बर एक में आ गये, सत्ता में आ गये तो बहुत अच्छा, नहीं तो सत्ता के नजदीक रह कर जो मलाई मेवा मिल सके उस को चाट कर अपनी जिन्दगी गुजार लो । इसलिये हिन्दुस्तान में जो सुविधा भोगी वर्ग पैदा हो गया है यह सुविधा भोगी वर्ग जो भोग के रास्ते से देश के निर्माण का रास्ता खोज रहा है और इस रास्ते से देश को बनाने का सपना देख रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि इस रास्ते से देश का निर्माण नहीं होगा । हमारे विचार और श्री भूपेश गुप्त के विचार बहुत से मामलों में एक रहते हुए भी कई जगह इन बुनियादी सवालों पर बुनियादी रूप से अलग-अलग तरह के हो सकते हैं । हमारा रास्ता तो स्वतंत्र गांधीवाद का रास्ता है । मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्री भूपेश गुप्त जी को कि उन्होंने एक ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक को सदन में लाने का काम किया है जिस पर हिन्दुस्तान में बहस होनी चाहिए। न केवल राज्य सभा में इस पर बहस हो बल्कि इस के बाद मैं चाहूंगा कि देश के अन्दर अखबारों के मार्फत इस पर बहस हो। लेकिन कौन अखबार वाला बहस करायेगा इन सवालों पर ? इन सवालों के लिये क्या टाइम्स आफ इंडिया, स्टेट्समैन या इंडियन एक्सप्रेस में जगह मिलेगी ? इंडियन एक्सप्रेस तो अपना टावर बनाने के लिए बेहाल हो रहा है, कोई अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिये बेहाल हो रहा है, कोई कुछ और करने के लिये बेहाल हो रहा है। तो इन सवालों को अखबार में लाने के लिये उन के पास जगह कहां है ? इन सवालों को पैदा करने के लिये उन के पास जगह कहां है ? उन को तो अपने मन के लायक सवाल चाहिए, उन को तो अपने मन के लायक बातें चाहिएं । उनको वह अपने अखबारों में छापेंगे । इस तरह के बुनियादी सवालों को उठाने के लिये उनके पास जगह नहीं है और खास कर मेरे जैसे लोगों की बात जो राज्य सभा, लोक सभा या विधान सभाओं में पहुंच जाते हैं और गंवई गांव की भाषा में अपना निवेदन करते हैं उन के लिये तो उन अखबारों में कतई जगह नहीं होगी । हम लोग तो गिटपिट बोलना जानते नहीं हैं । मैं जितना बोल रहा हूं उतना ही अगर गिटपिट में बोल पाता, दैट शैट बैट पैट में कह पाता तो यहां पर ही बहुत से लोग कहते कि हुकमदेव नारायण बहुत बेस्ट स्पीकर हैं । इसलिये ही मैं इन सवालों को उठाना चाहता हूं । मैं गांव का बसने वाला आदमी हूं । गंवई गांव की भाषा में अपने देहात की, गांव वालों की बोली में उन की बात को, उन की आवाज को

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

इस राज्य सभा में रखने के लिये आया हूं। उन की आवाज को यहां पहुंचा कर लोगों के दिमागों को चौंकाने का मुझे मौका मिला है और मैं राज्य सभा में आकर अपने तमाम माननीय सदस्यों से यह बिनती करूंगा कि काश इस राज्य सभा में बंगाल के भाइयों के मुंह से बंगाली निकलती, तमिल नाडु के भाइयों के मुंह से तमिल निकलती, कहीं कन्नड़ में बातें निकलतीं, कहीं मलयालम में बातें निकलती, उड़िया में निकलतीं, कहीं मराठी में बातें निकलतीं और इस भारत माता की गोद में जो विभिन्न प्रकार की भाषाओं के फूल खिले हुए हैं उन हर फूलों का स्वरूप इस राज्य सभा में देखने को मिलता और भारत माता का असली स्वरूप हम देख पाते। लेकिन हम खुद अपने गांव वालों की भाषा का निरादर करते हैं। हम खुद उनकी जबान का निरादर करते हैं। हिन्दी बोलने, उड़िया बोलने, मराठी बोलने, बंगला बोलने, अरबी बोलने, फारसी बोलने, मलयालम बोलने, तमिल बोलने, तेलगू बोलने, कन्नड़ बोलने में हम खुद इनफीरियरिटी कम्पलैक्स से पीड़ित हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो हम कैसे गांव वालों की भाषा राज्य सभा में बोल सकते हैं। याद रखिये अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति पर खर्चा कम होता है, उनको कम सुविधाएं मिलती हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि अमेरिका का राष्ट्रपति बहुत बड़े देश का राष्ट्रपति है। उसको जरा सी हुंकार मारने से सारी पृथ्वी हिल पड़ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति के एक हुंकार करने से पूरा प्रबन्ध हिल पड़ता है। उस देश का राष्ट्रपति चार एकड़ जमीन पर बने बंगले में रहता है और इस देश में उनके बोलने से चूहा तक नहीं भागता, बिल्ली तक नहीं भागती, गीदड़ तक नहीं भागता, सियार तक नहीं भागता। यहां का राष्ट्रपति 700 एकड़ जमीन पर बने बंगले में रहता है। अगर चार एकड़ जमीन पर बने बंगले में रहने वाले राष्ट्रपति का देश बलवान हो सकता है तो यहां का राष्ट्रपति जो एक प्रांत को घेरे में डाल कर चहार दीवारी बना कर रहते तो क्या इस देश का राष्ट्रपति महान राष्ट्रपति हो सकता है। मान न मान मैं तेरा मेहमान। अपनी पीठ अपने हाथ से थपथपाने से क्या कोई बलवान बन सकता है। क्या वह इस देश को इतिहास में तथा इन साइक्लोपीडिया में नाम लिखा लेगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति पर उतना खर्चा नहीं होता। इंगलैंड के प्रधान मंत्री को ही ले लें। उनके प्रधान मंत्री के बंगले पर, उनकी शान-शौकत पर जो खर्चा होता है और हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति पर जो खर्चा होता है दोनों के आंकड़े निकाल कर देख लें कि किस पर ज्यादा खर्चा होता है। मैं जानता हूं सरकार जवाब नहीं देगी। मैं चाहूंगा सरकार इसकी पूरी तफसील से जांच कराये, पड़ताल कराये। राजदूतों को खबर भेजे कि वे अपने दूतावासों से इस बारे में सारे आंकड़े इकट्ठे करके भारत सरकार को भेजें। जब भारत सरकार के पास ये आंकड़े आ जायेंगे तो पता लगेगा कि कहां-कहां कितना-कितना खर्च होता है।

चीन के माओ-त्से-तुंग को मैं सौ-बार, हजार बार सलाम करना चाहूंगा। चीन के माओ-त्से-तुंग ने अपने देश को शक्तिशाली बनाया। वह इतना शक्तिशाली होने पर भी एक छोटी सी कोठरी में रहे। एक छोटे से मकान में रह कर अपने हाथ से कपड़ा खींचने काम करते रहे। अपना खाना बनाने का काम खुद करते थे। वह पैदल या साइकिल पर चल कर देश के नवनिर्माण का कार्य करते थे। देश का आदर्श वह आदमी बना सकता है। उपसभाध्यक्ष जी, देश में बसने वाले करोड़ों नौजवानों ने माओ-त्से-तुंग को लाल सलामी देना शुरू किया। केवल वह बाहरी बात नहीं थी उसमें भीतरी बात भी थी। चीन का एक महान नेता छोटे से बंगले में रहेगा। चीन का एक महान नेता उतना ही कपड़ा पहनेगा जितना उस देश के आम आदमी की आवश्यकता

है। चीन का महान नेता वैसा ही खाना खाएगा जो आम जनता खाती है। चीन का नेता वैसा ही रहेगा जैसे उस देश की जनता रहती है। चीन के नेता की वही भाषा, भूसा, भोजन भवन होगा जसे उसकी आम जनता की है यानी लोक भाषा, लोक भूसा लोक भवन। इसी व्यवहार के कारण उसने नौजवानों को आकर्षित किया। दुनियां के नौजवानों को अपनी ओर खींचने का काम किया और हम यहां भोग में पड़े हुए हैं। रात-दिन भोग में रहते हैं। कई आदमी दिन में तीन-तीन बार धोती-कुर्ता बदल कर चलते हैं। औरतें दिन में 100-100 साड़ियां बदलती हैं। लोगों को दिखाने के लिये कपड़ा पहना जाता है। यह देखते हैं कि किस टाइम पर कैसा कपड़ा पहना जाए, कौन रंग की साड़ी पहनी जाए, कौन रंग का ब्लाउज पहना जाए, कौन रंग की टोपी पहनी जाए। किस कपड़े पर कैसी दृष्टि पड़ेगी इसको देख कर कपड़ा पहना जाता है। ग्रह नक्षत्र निकाल कर कपड़े बदलने और पहनने का काम इस देश में होता है। मैं चाहूंगा कि और सवालों को देखने से पहले इसको देख लें। उपसभाध्यक्ष जी, एक तरफ देश के अंदर जो भोगवृत्ति बढ़ रही है उस भोग वृति को रोकना होगा। इस भोग के रास्ते पर चलने वाले लोगों को सावधान करने के लिए गांव से राज्य सभा में एक साधारण आदमी आया है। ऐ, दिल्ली नगरी में बसने वालों, भोग की नगरी में बसने वालो, जरा उन गांवों की तरफ भी ध्यान दो जहां पर लोगों को दो रोटी भी खाने के लिए नहीं मिलती है। करोड़ों की संख्या में हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो गरीबी और भूख की ज्वाला में जल रहे हैं। यह ज्वाला अब आगे बढ़ने वाली है और यह दिल्ली नगरी भी इस ज्वाला से बचने वाली नहीं है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि आप भोग के रास्ते को छोड़िये। हमारे देश में न केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल को त्याग का रास्ता अपनाना होगा, बल्कि भारत की संसद् में रहने वाले और विधान मंडलों में रहने वाले लोगों को भी त्याग का रास्ता अपनाना होगा। इन लोगों पर कितना खर्च होता है, उस पर हमें गंभीरता-पूर्वक सोचना चाहिए। हमारे देश की राष्ट्रीय आय का कितना हिस्सा राजशाही नौकरशाही और व्यापार-शाही पर खर्च होता है, इसको देखने की जरूरत है। हिन्दुस्तान की पूंजी का, राष्ट्र की आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन लोगों की सुख-सुविधाओं पर खर्च हो जाता है। अगर हमें अपने देश का आगे बढ़ाना है तो हमें त्याग का रास्ता अपनाना होगा, गांधी का रास्ता अपनाना होगा। हमारे देश में 85 फी सदी से भी अधिक लोगों को आधे पेट रोटी भी नहीं मिलती है। गांवों के अन्दर अगर किसी किसी को एक रात का एक रोटी मिल जाती है तो उसको इसका पता नहीं होता है कि कल दिन में रोटी मिलेगी या नहीं। इस प्रकार की स्थिति हमारे देश में चल रही है। आप बंगाल में चले जाइये, आसाम में चले जाइये, बिहार में चले जाइये, गांवों के अन्दर लोग इस प्रकार के खाद्य-पदार्थों को खाते हैं जो वास्तव में खाद्य-पदार्थ हैं ही नहीं। महुआ खाकर लोग अपना जीवन चलाते हैं। जिस देश में इस प्रकार की स्थिति हो वहां लोग और खासतौर पर ऊंचे पदों पर रहने वाले लोग ऐशो-आराम की जिन्दगी बितायें, यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है आज हमारे देश में हालत यह है कि लेबर प्राब्लम्स पर लोग थिसेस लिख देते हैं, लेकिन थिसेस लिखते हैं एयर कन्डीशन्ड घरों में बैठ कर। जिनका बाप कभी लेबर नहीं था, जिनके खान-दान में कोई लेबर नहीं था, जिन्होंने कभी मजदूरी नहीं की, जिन्होंने कभी मेहनत करके पसीना नहीं बहाया, वे लोग थिसेस लिखते हैं—लेबर प्राब्लम्स इन इंडिया। जिन्होंने कभी हल नहीं चलाया, जो कभी मजदूरों के बीच मे नहीं रहे, वे मजदूरों की और गरीबों की अभावों की जिन्दगी को कैसे समझ सकते हैं? आज हमारे देश में इस बात की जरूरत है कि हमारी

[श्री हुकमदेव नारायण यादव]

नीतियां व्यवहारिक होनी चाहिएं और हमें व्यवहारिक होना चाहिए।

श्रीमन्, मेरा कहना है कि जिस प्रकार से गंगा नदी पवित्र गंगोत्री से निकल कर बहती जाती है और उसमें कई नदी-नाले, गन्दे और अच्छे सभी मिलते जाते हैं और गंगा पवित्र बनी रहती है उसी प्रकार से हमारे देश में राष्ट्रपति और राज्यपाल, संसद् और विधान मंडल भी गंगोत्री के समान पवित्र होने चाहिएं। अगर ये स्थान पवित्र होंगे तो सारे देश में पवित्रता की गंगा बहेगी। हमें भोग का रास्ता छोड़ कर त्याग का रास्ता अपनाना होगा। त्याग और भोग, इन दोनों प्रश्नों पर हमें विचार करना होगा। हमें भोग का रास्ता छोड़ना होगा और त्याग का रास्ता अपनाना होगा। मैं चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्यों को इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के खर्च को किस प्रकार से कम किया जाय। हमारे देश में खर्च की सीमा बांधनी होगी। हमारे देश में जो फजूलखर्ची है उसको रोकना होगा। हमारे देश में फजूलखर्ची के कारण लगभग दो हजार करोड़ रुपये बरबाद हो जाते हैं। यह बात मैं नहीं कहता हूं। लोक सभा में डा० राम मनोहर लोहिया ने आंकड़े देते हुए यह बताया था कि हमारे देश में किस प्रकार से फजूलखर्ची की जाती है। आज जरूरत इस बात की है कि इस फजूलखर्ची को रोका जाय। खर्चे की हद बांध दीजिये तो याद रखें कि खर्चे की हद लगाने में, खर्चे पर पाबन्दी लगाने से इस देश में कोई दो हजार करोड़ रुपये सालाना की बचत होगी और अगर दो हजार करोड़ रुपये आप अपने देश में बचा लेंगे तो देश का नव-निर्माण कर सकेंगे। पैसे-पैसे के लिये अमेरिका के आगे हाथ फैलाते हो, रूस के आगे हाथ फैलाने जाते हो, एक छोटा सा देश है जर्मनी उसके यहां भीख मांगने जाते हो, छोटा सा देश है जापान, वहां भिखमंगे बन कर जाते हो, एक छोटा सा देश है पोलैंड, वहां भिखमंगे बन कर जाते हो। शर्म नहीं आती है।

मांगना काम है छोटों का,
भिखमंगे अनादर पाते हैं।
भगवान भी बौना बनते हैं,
जब दान मांगने जाते हैं।

भगवान को भी बौना बनना पड़ा जब वे भीख मांगने के लिये गये। जो ईश्वर है, जो भगवान है उसको भी भीख मांगने के लिये छोटा रूप धारण करना पड़ा। भिखमंगे का सम्मान दुनियां में आज तक कहीं नहीं हुआ है। आप भिखमंगे हो, दुनिया की नजर में भिखमंगे हो, दुनियां की नजर में कोई इज्जत नहीं है, दुनियां की नजर में भूखे हो, दुनियां की नजर में रोटी के लिये हाथ फैलाते हो, गेहूं के लिये हाथ फैलाने जाते हो, कपड़े के लिये हाथ फैलाने जाते हो, दुनियां के अन्दर और दूसरे सामानों के लिये हाथ फैलाने जाते हो, झोली फैलाने और भीख मांगने जाते हो। भिखमंगे की संसद में आने वाले माननीय सदस्यों इस भिखमंगे देश के हम भिखमंगे हैं और केवल मुट्ठी भर लोग भिखमंगों के खून पर अपने को शहंशाह साबित करना चाहते हैं, छाती तानकर चलते हैं। हमें इसमें कोई गर्व नहीं करना चाहिए बल्कि शर्म से हमारा सर झुक जाना चाहिए। हमें शर्मिन्दा होना चाहिए न

कि गर्व करना चाहिए इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि दुनिया से भीख मांगते फिरते हो, हाथ फैलाते हो और अपने देश के अन्दर सुविधाभोगी लोगों पर, सामन्ती प्रवृत्ति पर, भोग पर तुम देश का अरबों रुपया खर्च करने का काम करते हो । अपने देश के अन्दर भोग के ऊपर सारा खर्च हो रहा है । यह देश चारवाक के सिद्धान्त पर चल रहा है । चारवाक ने कहा है कि:

यावद् जीवेत् सुखम् जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृतम् पीवेत् ।

अर्थात् जब तक जियो सुख से जियो कर्ज लेकर घी पिओ । कर्ज लाओ और खूब घी पिओ । इस तरह इस देश में चारवाक के सिद्धान्त पर, उसके दर्शन पर विश्वास करने वाले तुम दूसरे देशों से कर्जा लेते हो और दूसरे देशों से भीख मांग लाते हो और सारा पैसा भोग पर खर्च करते हो, विलासिता के ऊपर खर्च करते हो । देश के अन्दर जो एक प्रतिशत लोग हैं, सुविधाभोगी लोग उनके विकास और उनकी उन्नति पर खर्च करते हो और देश के अन्दर जो 99 प्रतिशत लोग हैं उनको दबाने का काम करते हो, उनको मिटाने का काम करते हो । अगर हिन्दुस्तान में किसी विदेशी की आंख पर पट्टी बांध कर उसको बिहार के कोसी इलाके में घुमा दिया जाय, दक्षिण में घुमा दिया जाय, बिहार के छपरा, चम्पारन और मोतिहारी इन जगहों पर घुमा दिया जाय और उसके बाद उसको लाया जाय और बिहार के राज्यपाल के घर में आकर आंखों की पट्टी खोल दी जाय और उसको कहा जाय कि बोलो तुम कहां हो । वह यह कहेगा कि मैं चल आया हूं अमेरिका के किसी इलाके में, मैं बिहार में नहीं हूं । एक विदेशी की आंखों में पट्टी बांध दीजिये और उसको राजस्थान में ले जाया जाय, मध्य प्रदेश में ले जाया जाय, उनको गरीबों के इलाके में ले जाया जाय, अनेकों गलियों और आदिवासियों के मुहल्ले दिखा दिये जायें, हजारों झोंपड़ियां दिखा दी जायं, मजदूरों की झोंपड़ियां दिखा दी जायं गरीबों के घर दिखा दिये जायं और फिर आंखों पर पट्टी बांध कर राष्ट्रपति भवन में जो वहां बड़ा सा हाल है जिसमें निमंत्रण कभी-कभी संसद् सदस्यों को चाय पानी पीने के लिये दिया जाता है, इस हाल में लाकर उसके आंख की पट्टी खोल दी जाय तो उसको यकीन नहीं होगा कि मैं हिन्दुस्तान में हूं । उसको ऐसा लगेगा कि मैं परलोक में चला आया हूं, किसी स्वर्गपुरी में चला आया हूं, किसी स्वप्न लोक में आ गया हूं । यह भारत का अंश नहीं है, हिन्दुस्तान का अंग नहीं है । इसलिये हिन्दुस्तान को बनाने के लिये अगर चाहते हो कि हिन्दुस्तान मजबूत बने, हिन्दुस्तान बलवान बने तो जब देश में बसने वाले सौ आदमियों में से 90 आदमी बलवान बनेंगे तभी देश बलवान बनेगा, सौ में से अगर 10 आदमियों को खिलाते-खिलाते आप इतना मोटा कर दें कि मोटापे से वह खाट पर से न उठ पाये और 90 आदमी भूख के कारण इतने कमजोर हो जायं कि उठने से लाचार हो जायें और 10 आदमी खा-खा करके मोटापे से इतने लाचार हो जायें कि उठ नहीं सकेंगे, इससे देश के सौ फी सदी लोग रोगी हो जायेंगे, आलसी हो जायेंगे । बहुत से लोग मोटापे से लाचार हो जायेंगे और बहुत से लोग कमजोरी के कारण लाचार हो जायेंगे । इसलिये अगर देश को बनाना है तो देश के बारे में ऐसी योजना बननी चाहिए जिससे देश के 100 में से 90 आदमी मजबूत बन सकें, सौ में से 90 शक्तिशाली बन सकें, 100 में से 90 आदमी विद्वान बन सकें, सौ में से 90 आदमी तेजस्वी बन सकें, 100 में से

[श्री हुक्म देव नारायण यादव]

90 आदमी प्रभावशाली बन सकें । एक-एक हरिजन के घर से भोला पासवान शास्त्री, राम विलास पासवान और जगजीवन राम जैसे आदमी निकालने के लिये अगर काम करोगे जिससे कि इस देश का हरिजन मजबूत हो, आदिवासियों के घर में से ऐसे आदमी निकलें, मुझे पता नहीं कि मकवाणा साहब आदिवासी हैं या नहीं हैं ।

अगर आदिवासी हों तो इस तरह से सैंकड़ों आदिवासी झोंपड़ियों से निकलेंगे तभी जा कर देश मजबूत बनेगा । इसलिये मेरी बात को कांग्रेस (आई) में बैठे हुए सीताराम केसरी जी ज्यादा समझ पायेंगे, श्री रामानन्द यादव जी ज्यादा समझ पायेंगे, लेकिन उन्हीं की तरफ बैठे हुए श्री महेन्द्र मोहन मिश्र जी नहीं समझ पायेंगे, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी नहीं समझ पायेंगी । क्योंकि मेरे दर्द को वे नहीं जानते हैं । मैं जिस दर्द से पीड़ित हूं उस दर्द से केसरी जी भी पीड़ित रहे, रामानन्द यादव जी भी पीड़ित रहे हैं । हमारे नेता भोला पासवान शास्त्री जी बैठे हैं, इन्होंने जितना देखा है शायद दुनिया में... *(Interruptions)*. इसलिये उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं । मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आज देश के अन्दर 100 में से 90 आदमी बलवान बनेगा, तब देश मजबूत बनेगा, देश तेजस्वी बनेगा, प्रतिभा सम्पन्न बनेगा । तब देश मजबूत बनेगा । अगर देश में 10 आदमी मजबूत हो जाए और बाकी 90 आदमी कमजोर रहें तो देश कमजोर होगा । हिन्दुस्तान बार-बार गुलाम इसलिए होता रहा । आप हिन्दुस्तान का इतिहास उठा कर देख लें कि हिन्दुस्तान बार-बार गुलाम क्यों हुआ । केवल आपसी फूट के कारण ही हमारा देश गुलाम नहीं हुआ । यह एक सत्य है । देश के गुलाम होने के और भी कारण थे । उस समय जो राजसत्ता चलाने वाले, राजघराने वाले लोग थे, वे भोग में सराबोर थे । हिन्दुस्तान के गांव में बसने वाले गरीबों का शोषण कर के अपने महलों के अन्दर भोग की जिन्दगी जीते थे । गांव में रहने वाले गरीब लोग यह समझते थे कि महलों में रहने वाले राजघरानों वाले हमारा खून चूसते हैं । वे समझने लगे कि यह विदेशी हम लोगों के मुक्तिदाता बन कर आए हैं । वे मौज की जिन्दगी बिता रहे हैं । इसलिए देश में बसने वाले भाइयों, मेरी आपसे प्रार्थना है, झोंपड़ियों में बसने वालों से हमारी प्रार्थना है... *(Interruptions)*

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : यादव जी, अभी एक घंटा हुआ है, आप अपना भाषण जारी रखिये । रुकिये मत ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : उपसभाध्यक्ष जी....

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : आप अपना भाषण जारी रखिये ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : भाषण तो मैं जारी रख लूं लेकिन और दूसरे माननीय सदस्य भी बोलने वाले हैं । आपने मुझे बोलने का ही प्रथम मौका दिया इसलिए मैंने इन सवालों को छेड़ने का काम किया । केवल यह एक मुद्दा नहीं है बल्कि कुछ दृष्टिकोण सामने आए हैं । इन दृष्टिकोणों पर बहस हो । हो सकता है कि जिन माननीय सदस्य ने इस विधेयक को सदन में रखा है मेरे दृष्टिकोण से, सभी बातों से वे सहमत हों या

न हों लेकिन सदन के सामने और भारत की जनता के सामने इसकी मार्फत एक नयी बात आये। लेकिन इस पर जम कर बहस करें क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे राष्ट्रपति जी ने भी कहा था कि मैं छोटे मकान में जाना चाहता हूं। वैसा छोटा मकान दिल्ली में शायद कोई है ही नहीं जहां वे चले जाएं। जैसे छोटे मकान में वे जाना चाहते हैं ऐसा छोटा मकान जरूर बनावें। यह मैं उनके प्रति कोई निरादर की भावना से नहीं कर रहा हूं। मैं भी किसान हूं और वे भी किसान हैं और जब वे यह बोले थे तो मैंने यह समझा कि किसान के हृदय से यह आवाज फूट पड़ी है। इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न को उठाया था, खर्च पर हदबन्दी का सवाल उठाया था। राष्ट्रपति और राज्यपाल तो प्रतीक हैं। इस प्रतीक होने के आधार पर राष्ट्रपति हिन्दुस्तान के सम्पूर्ण प्रशासन के सर्वोच्च पद पर माने जाते हैं। राज्यपाल राज्य के अन्दर संवैधानिक दृष्टिकोण से सर्वोच्च पद पर माने जाते हैं। इसलिए जब इन दोनों पदों के ऊपर आप नियंत्रण करेंगे, इनके खर्च को घटाने का सवाल करेंगे तो उसके साथ-साथ सब के खर्च घटाने का सवाल पैदा होगा और वह नीचे तक चलेगा। ऊपर से शुरू करिये।

इसलिए मैं कहता हूं गंगा गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री से शुद्ध धारा निकलने दीजिए। आज के जो खर्चे हैं दिन रात बढ़ रहे हैं। देश के अन्दर भोग की सामग्री पैदा कर रहे हैं। पूंजीपति देश के अन्दर भोग की सामग्री पैदा करा रहे हैं। देश को लूटने का काम करते हैं आप वे आंकड़े निकालिये। 1977 से मैं लोक सभा का सदस्य था। मैंने उस समय प्रश्न कर के भारत की सरकार से यह जानना चाहा कि सरकारी मकानों को सजाने पर दिल्ली में हर साल कितने रुपये लगते हैं। सरकारी मकानों की साज-सज्जा पर हर साल कितने रुपये लगते हैं, मंत्रियों के मकानों को सजाने पर हर साल कितने रुपये लगते हैं। इन सारे आंकड़ों को मैं इन प्रश्नों के जरिये निकालने का काम करता था। मैं इसलिए इन बातों को पूछता हूं कि जिससे यह पता लगे कि हिन्दुस्तान का कितना पैसा इधर खर्च हो रहा है, कितना पैसा इसमें लगाने का काम हो रहा है। क्या इसलिए कि आप इस देश को पैसे-पैसे के लिए मोहताज कर दें। हमारे हाथ में पैसा नहीं है। कहते हो मेरे पास पैसा नहीं है और 14 सौ या कितने का डेफिसिट बजट आपने भारत की संसद में रख दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि चाहे विदेशी पैसा न भी मिले परन्तु देश का निर्माण कब होगा। जब देश को बनाने के लिए हम अपने आपको नियंत्रित करेंगे। गांव के अंदर एक साधारण आदमी जो गांव की झोपड़ी में रहता है, अगर अपने घर में खर्चे की कमी हो जाती है तो वह खर्चे की कटौती करके आगे का निर्माण करता है। इसलिए आप सही बात को सोचें कि हमको अगर पैसा बचाना है, देश का निर्माण करना है, देश के अंदर करोड़ों बेरोजगारों के हाथों में काम देना है तो हम क्या करें। हमारे देश के अंदर में इतनी जमीन है परन्तु उसकी सिंचाई का इंतजाम नहीं है। इन्द्र के भरोसे से भारत में हमारी खेती पड़ी रहती है, बाढ़ से फसलें मारी जाती हैं। बाढ़ से अगर देश को बचाना है, रोजी रोजगार देना है तो इस देश के अंदर पैसा बचाने का काम करें। पैसा कहां से बचेगा। जिस रास्ते से बड़े लोग चलते हैं देश के तमाम लोग उसका अनुकरण करते हैं। हम अगर बचाने का काम करेंगे, हमारी जिंदगी अगर सात्विक वाली जिंदगी होगी, हमारे ऊपर पैसा कम खर्च होगा, हम अगर ठीक से रहेंगे तो देश के लोग उसका अनुकरण करेंगे। लेकिन अगर हम जितने लोग हैं वे सब शराब पीकर नशें में नाचने लगेंगे तो देश के अंदर में शराबबंदी नहीं होगी। कौन सुनने वाला है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरे को उपदेश देने का सवाल नहीं है बल्कि त्याग के रास्ते पर चलो।

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

श्रीमती इंदिरा गांधी का एक लीफ्लेट जब राज्य सभा में आया तो मिला, उस एजेंडा पेपर के साथ एक किताब है और उसमें अंग्रेजी में था, मैंने देखा कि 'आस्टरिटी' या कुछ शब्द था जिसके बारे में उन्होंने चार-पांच पन्ने लिखा था उसको मैंने बहुत पढ़ने के बाद कुछ सोचा। मुझे कुछ हंसी भी आयी और कुछ रोना भी आया। मैं हंसा इसलिए कि जहां उपदेश दिये जा रहे हैं क्या वहां यह लागू हो रहा है और रोया इसलिए कि दूसरों को सुनाने का काम हो रहा है। अपने को भोग में सरोबार करने का काम हो रहा है अर्थात् रास्ता भोग का और बात त्याग की। यह त्याग नहीं चलेगा। अगर त्याग के रास्ते पर चलना है तो जीवन में त्याग करना पड़ेगा। यह देश गांधी का देश है। गांधी जी ने हिम्मत के साथ कहा कि हिन्दुस्तान के एक आदमी का जितना हिस्से में कपड़ा आता है हम उससे ज्यादा कपड़ा उपभोग नहीं कर सकते हैं। यह देश बनाने का काम है। याद रखिए हिन्दुस्तान को हिलाने का काम महात्मा गांधी जी ने किया, गौतम बुद्ध ने किया, कबीर ने किया, नानक ने किया, महावीर ने किया। हिन्दुस्तान को हिलाने के लिए इस देश के अंदर त्याग के रास्ते पर चलने वाले लोग थे, वे देश को बलवान, सुखी और सम्पन्न बनाना चाहते थे। उन्होंने देश को झकझोरने का काम किया। देश के वातावरण में लोगों की आवाज इनके मुहं से निकल रही थी। इसलिए सभापति महोदय, यह जो विधेयक आया है, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं यह मांग करता हूं सदन के द्वारा कि सदन इस विधेयक पर न केवल विचार करें बल्कि सदन इस विधेयक को पास भी करे। इस विधेयक को पारित किया जाय और पारित करने के साथ-साथ इससे जो एक नयी विचार धारा देश के अंदर चलेगी, जो देश के अंदर आज निराश लोग हैं, इससे उन निराश लोगों में आशा का संचार होगा, आशा की किरण जगेगी। उन लोगों को विश्वास होगा अब हिन्दुस्तान की संसद से त्याग का भाव निकलने वाला है, त्याग की धारा बहने वाली है और आज त्याग के रास्ते पर चल कर सम्पूर्ण हिन्दुस्तान का नव-निर्माण होगा। इसलिए मैं इस विधेयक का न केवल समर्थन करता हूं बल्कि मैं सदन से अनुरोध भी करता हूं कि सभी माननीय सदस्य इसको कोई दल की बात न माने और पास करें। कांग्रेस 'आई' के लोग क्यों नहीं अपनी तरफ से इसको मान लेते हैं, क्यों नहीं इस तरह का बिल अपनी तरफ से पेश करते हैं। वे नहीं पेश कर सकते हैं। परन्तु इसी बिल को अपना मान लें। आपका यह बिल पास हो और इस रास्ते पर देश चले। इसी रास्ते से देश बन सकता है। देश को आगे बरबाद मत होने दीजिए, देश को अब रसातल में मत जाने दीजिए। याद रखिए मैं अंत में सभा से यह निवेदन करूंगा कि यह देश डूब चुका है, टूट चुका है, यह देश रसातल की ओर बढ़ चला है, रुक जाइये। जहां तक देश डूब चुका है उससे आगे इसको अब मत डूबने दीजिए। यह देश जितना टूट चुका है, उससे ज्यादा इस देश को मत टूटने दीजिए। यह देश जितना रसातल में चला गया है, उससे ज्यादा आगे इस देश को और रसातल में मत जाने दीजिए। अभी भी समय है। आप अभी भी रोक सकते हैं। नहीं रोकोगे तो आने वाले दिनों में, कोई दो, चार, पांच सालों के अन्दर नहीं, एक या दो साल के अन्दर ही इस देश के अन्दर जो भोग और त्याग के रास्ते पर लड़ाई चल पड़ी है, उससे भयानक दुर्घटना होने वाली है और न जाने इस देश में कैसा वातावरण बनने वाला है। इसलिए उठती हुई आवाजों को देखिए, उठती हुई आवाजों को पकड़िये, करोड़ों दिलों की, पीड़ित और शोषित आदमियों की जो आवाज है, उस वाणी को पकड़िये, मूक वाणी को पहचान कर के बोलो, मूक की भावना बन कर सब के अन्दर प्रस्तुत हो।

मूक जो आज रोटी रोजी, कपड़े के लिए तरस रहा है, उनको रोजी-रोटी, कपड़ा देने के लिए हमें अपनी योजना बनानी चाहिए, अपना पैसा खर्च करना चाहिए न कि राज्यपाल, राष्ट्रपति, संसद् सदस्यों, विधान सभा के लोगों और सरकारी कर्मचारियों के ऊपर हिन्दुस्तान के राजकोष का संचित निधि का पैसा, बढ़ाते बढ़ाते हम देश का खजाना ही समाप्त न कर दें, बल्कि दूसरी ओर भी देखें जहां से हमें शक्ति मिलती है, जो शक्ति का स्रोत है। उन झोपड़ियों की ओर, किसानों की ओर भी देखें, उनकी आत्मा की आवाज को भी सुनें, तभी देश मजबूत बनेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और सदन से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को एक मत से, सर्व-अनुमति से पास करें।

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): Mr. Vice-CLairman, Sir, I am thankful to you for giving me an opportunity to take part in this discussion. Sir. I am very glad indeed to speak on the Bill moved by hon. Bhupesh Gupta. On behalf of the DMK Party, I would like to express some of our views on this Bill.

Mr. Yadav who made an emotional speech here, said th rt since he speaks in Hindi his speeches are not covered in the Press. But that is not the fact. Sir, even when we, Members coming from the deep south, from Tamil Nadu and Kerala—even v. hen we speak in English, our speeches are hot at all covered in the Pres;; we do not find any publication o: our speeches in newspapers. At tht same time, we are at a terrible *h* ss in the House because this Housa has become an assembly of Hindi speaking persons. Members who can speak in English also speak in Hindi, and we are unable to follow then-,. We are unable to follow the translation also. That is another difficulty

AN. HON. MEMBER: Even the translation is not so perfect.

SHRI V. GOPALSAMY: That is another problem.

The salaries of the hon. President and the Governors should be reduced; this is the object of the Bill. I think, the persons who have occupied the prestigious Chair of the President have not received full amount of their salary. I think they have surrendered and they have received only a part of the amount. Why is it so? why do they not want to get the full salary? The Bill moved by Mr. Bhupesh Gupta will be welcomed by all. If the salary is reduced, I think the present President is not going to grudge it. I do not think it is proper to cast any aspersions on the present President in this discussion. He does not think himself great. He has been for eight years in British jails. He comes from peasant stock from the village. When he comes out of this office, he will, I think, definitely go to the fields. They do not want to get full salary. Not only that. They do not want to live in the present biggest palace in the world Like the previous Presidents, the present President has expressed his desire to mov© from the palace to a smaller bungalow. Why? There they cannot feel happy to stay in the biggest palace when more than half the population is suffering in huts and slums. This palace was built by the British imperialists just to exhibit their pomp and power—as a symbol of their power. During the freedom struggle, our great leaders assured that once they attained freedom, these palaces would be converted into hospitals. If it becomes a hospital, I think everybody will feel happy and everybody will welcome it. Not only the salary but also the huge cost of maintaining them is to be looked into. The huge expenditure to maintain the palace and the perapheranalia should be reduced. Many things were said about the basic structure of the Constitution during this discussion. I think Mr. Sankar Ghose was very correct in saying that the three principles—

[Shri Gopalsamy]

republicanism, democracy and secularism—are the three pillars on which our Government stands. But I And a dangerous tendency is being nur-turned today in regard to the concept of unitary character in our Constitution. Sir, I would like to say in no uncertain terms that the day we move towards the unitary character away from the federal character, the very concept of unity will be destroyed and the unity of our country will be in jeopardy.

The Villian of the piece is the Governor. I think the institution of the Governor is a total denial of the federal character in our county. How did the Governors come into picture? These Governors were appointed by the British as agents of the imperial power to suppress the masses in the provinces. We inherited the post of Governor from the British when we copied down the Govt, of India Act 1935, and the post of Governor was created. There was a debate in the Constituent Assembly about whether to elect the Governor or to nominate the Governor. There was a heated debate in the Constituent Assembly about this point. The great Pandit Jawaharlal Nehru opposed the election. They finally came to the conclusions that the Govenors should be nominated by the President. Now, the Constitution merely states that the Governors shall be nominated by the President, hold office at the pleasure of the President. So, they are nominated by the President. Sir. it will be very interesting to see the debates of the Constituent Assembly in which the great freedom fighter Mr. Mahavir Tyagi, said, that the Governor is the agent 01 rather he is the agency which will press for and guard the central policy. That is why the Governor's post was created. What happened? On so many occasions, this institution of Governor worked against the federal character of our country and also against the wishes of the people. 1 think you will remember that in the year 1952 when the first Assembly elections were held—at that time the State was called 'Madras' and not 'Tamil Nadu' and the credit for calling the State Tamil Nadu goes to Anna the Congress Party did not get the majority. Out of 322 seats, the Congress got only 155 seats only and the remaining 167 seats went to the opposition parties such as Communists, Independents, Socialists and other parties. They formed a united front under the leadership of Mr. Praka-sham. He informed the then Governor, Sri Prakasa, that he got the support of 167 MLAs, and he expected that he will be called to form the Government. And what happened, you know well. Sri Prakasa, the then Governor instead of calling Prama-sam to form the Government nominated Rajaji to the Legislative Council through the backdoor to make him the Chief Minister. You will be interested to know that the very Sri Prakasa was appointed as Governor by the same Rajaji when he was the Governor-General. So,(Rajaji was called to form the Government. Though Prakasam had the mjority of 167 ML As, he did not get the opportunity. This is the role played by the Governors in our country. We know on how many occasions in West Bengal and Kerala, the democracy was butchered by the Governors.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY (West Bengal): At that time, when he took over, Rajaji got the majority.

SHRI V. GOPALSAMY: It was after that. There were some Independents who were supporting Mr. Prakasam. If Mr. Prakasam had been called, they would have supported Mr. Prakasam. That is your opinion and I differ with you. On what ground did he call Rajaji to form the Government? And what happened in the year 1968? Mr. Ananthasayanam Ayyangar was the Governor of Bihar State. What happened then? Ther«

was a pressure from the top to topple the United Frost Government. He refused to oblige and he lost the post Mr. Ananthasa 'anam Ayyangar said, "My only mistike was that I did not act as some otl er Governors did. If I had, then Ii coi Id have continued as Governor for 15 years."

Sir, Mr. Bin pesh Gupta was very correct when h j said thnat the salary of the Governi r must be reduced. I want to say tlat the institution of Governors should be abolished. That is our view. Y iu may say that there will be a vacu am then, and how can you function. Sir, I am a student of politics, i am not a professor. Many learned professors and parliamentarians are here J am a student. I am so young that I v.^-ant to hear from you. I want to studj. But at the same time, I have got eve y right to putforth my view. Sir, Wes Germany is a federal country. There is no Governorship there. Only Irdia, Canada, Australia and some othe countries have Governors. West Germany is a federal country and they have no Governors. There is no C) ief Minister. The Head of the State s called the Minister President. If the Head of the State wants to quit or if the Opposition wants to bring a no confidence motion, through the same resolution, they will simultane iusly seek for the election of the Minister President. That is called a 'cc nstructive vote of no-confidence mo ion'. So, there is no vacuum. So, 1 :t us have a rethinking on this. The post of Governor itself should be abolished. Not only that, Sir. You w U be shocked and surprised to know how much money is spent on Gove mors and on the maintenance of Raj Bhavans. I want to quote from the book "India's Socialist Prices"—how beautifully titled—by Benedict Cost i. At page 30, he says: "For the mai: itenance of Raj Bhavan only, Tamil I adu gets Rs. 70,000 per year. Mahar; shtra gets Rs. 1.13 lakhs, West Bengal—Rs. 87,500, Uttar Pradesh—Rs. 93,000, Bihar—Rs. 50,900 and Orissa—Its. 46,000." And for the entertainment of guest—another category—and for tour expenses the Governors get per year in Tamil Nadu Rs. 3.20 lakhs, in Maharashtra Rs. 5 lakhs, in West Bengal Rs. 3.70 lakhs, in Uttar Pradesh Rs. 3 lakhs, in Punjab Rs. 2 lakhs, in Andhra Pradesh Rs. 2.73 lakhs, in; Kerala Rs. 1.67 lakhs, and it goes on like that. *(Interruptions.)* Madam please listen And for maintenance of gardens and for electricity and water charges a Governor gets Rs. 3.35 lakhs in Tamil Nadu, Rs. 6.50 lakhs in Maharashtra and Rs. 5.90 lakhs in West Bengal. And, Sir, this is treated as a charged item. What does it mean—a charged item? It means that the State has no say in this matter, but at the same time the State exchequer is burdened.

One Mr. Subrata Sarkar in his book "The Centre and the States" has asked the question. "Why the State Government should bear the entire cost of the Governor's establishment, particularly when the State Legislature has no control over such a huge amount of money even though it is included in the State Budget?" So, they have no say in the matter. When the Governors post is an agency of the Centre, as has been said by Mr. Mahavir Tyagi, why can not the Centre meet the expenditure? These are the questions. Huge amounts of money are being spent. These Raj Bhawans are white elephants swallowing the taxpayer's money. So the institution should be abolished.

Sir, in this context it will be very relevant if I quote a few lines from I no less a person than the great freedom fighter, Mr. J. B. Kripalani. Hesays:

"These Swaraj Governors occupy the same palaces that were occupied by their Imperial predecessors. Often these cover more than a quarter mile of land in overcrowded cities. Gandhi had said that under Swaraj these palaces would be turned into hospitals for the poor. But they have been turned into

[Shri V. Gopalsamy]

rest houses for the old and weary and those rejected at the polls. As gentlemen and partymen, beholden to the Central leaders for their appointment, it has been but natural for the 'Swaray Governors' to regard themselves as the 'agents' of the Centre rather than heads of the constituent units of the Indian Union, and look to New Delhi for 'aid and advice' as and when confronted with a crisis, or to equate the interests of the State or the country with those of the Congress Party".

Sir, with these few words I conclude and support this Bill.

श्री पी० एन० सुकुल (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह हमारे लिए गौरव की बात है कि मैं इस सम्माननीय सदन में पहली बार एक ऐसे विषय पर बोलने का अवसर पा रहा हूं कि जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमारे श्री भूपेश गुप्त जी ने जो प्रश्न उठाया है कि हमारे राष्ट्रपति को या हमारे राज्यपालों को जो तनख्वाह मिल रही है, वह उतनी ही मिलनी चाहिए या उस से कम मिलनी चाहिए, बल्कि उन का तो प्रस्ताव है कि वह कम मिलनी चाहिए, तो मैं अत्यन्त विनम्र शब्दों में भूपेश दा को यह बताना चाहूंगा और आप के माध्यम से इस हाउस को बताना चाहूंगा कि मैं इसके समर्थन में कतई नहीं हूं। यह मसला एक हजार, दो हजार, तीन हजार रुपये का नहीं है, यह दो तीन हजार रुपये का मसला नहीं है, यह मसला है हमारी संस्कृति का, यह मसला है हमारी परम्पराओं का, हमारी नैतिकता का और हमारे आत्म सम्मान का ोर हमारे राष्ट्र के गौरव का। आज प्रेजीडेंट किसी पार्टी का नहीं होता है। प्रेजीडेंट किसी संगठन का नहीं होता है। अगर हम में से किसी भी पार्टी का सदस्य यह समझता है कि प्रेजीडेंट बहुत ज्यादा तनख्वाह पाता है, बहुत लेविशली रह रहा है, ठीक है कम होना चाहिये, लेकिन महज इसलिये हम प्रेजीडेंट की तनख्वाह कम करना चाहते हैं ताकि देश में समाजवाद ले आयेंगे, यह आपका दुःस्वप्न होगा।

मुझे दुःख होता है जब मैं अपने विरोधी पक्ष के नेताओं को यह कहते हुए सुनता हूं। तीन वर्ष तक इस देश में विरोधी सरकार रही सन् 1977 से लेकर 1980 तक। मैं अपने विरोधी साथियों को यह बताना चाहता हूं कि मैं नहीं जानता और कितने लोग हैं, बहुत से होंगे लेकिन मैं भी पूरे 19 महीने इमरजेंसी में मीसा में बन्द रहा। I think I am the onl yman in the Treasury Benches here who spent as many as 19½ months in the jail under MISA during emergency. मेरी बात को हमारे विरोधी दल के साथी ध्यान से सुनें। हमारे यादव जी अभी बोले बहुत अच्छा बोले। यादव जी ने एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि ग्रामों में रहने वाला, अभावों से जूझने वाला, एक ग्रामीण हमारा जो भाई है वह क्या महसूस करता है, ऊंची-ऊंची तनख्वाह पाने वाले, बिरला, टाटा के बारे में वह क्या सोचता है, उन्होंने इस दर्द को महसूस किया और बहुत ही सीधे-सादे निश्छल शब्दों में उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया। लेकिन मैं अपने साथी यादव जी को बताना चाहता हूं कि वह उम्र में हम से कम होंगे। यहां मैं नया जरूर हूं लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यह दृष्टिकोण हमारे फ्रस्ट्रेशन को प्रकट करता है। आप देखते हैं कि

अमेरिका, वेस्ट जर्मनी या कहीं भी किसी देश के राष्ट्रपति के बारे में वहां के देश की संसद् में बैठकर इस बात की चर्चा नहीं होती कि राष्ट्रपति का वेतन कम कर दिया जाए और न ही कभी यह अखबारों में पढ़ा ।

[The Vice-Cb,iirmaa (Shri **Arviai** Ganesh **Kulkaru**) in the Chair],

श्री लाड़ली मोहन निगम (मध्य प्रदेश) : इम्पीचमेंट हो जाता है ।

श्री पी० एन० सुकल : इम्पीचमेंट जरूर होना चाहिये ।

Impeachment is another thing. It is the case of i commission. He has committed somt thing wrong and you can impeach hi n. That is your right and I do not challenge it

इम्पीचमेंट का सवाल नहीं है । इस पवित्र संविधान का हमारे देश के महान लोगों द्वारा निर्माण किया गया है । इसमें पंडित नेहरू, डा० राजेन्द्र प्रसाद, डा० अम्बेडकर आदि महान व्यक्ति थे । सन् 1947 में जब अंग्रेज यहां से गये तो इस देश में मुझे याद है कि एक रुपये का चार सेर गेहूं मिलता था । मैंने उस वक्त हाई स्कूल पास किया था और इन्टरमीडिएट में पढ़ रहा था । उस समय हमारे संविधान के महान निर्माताओं ने केवल देश के गौरव को, देश की परम्पराओं को, हमारे देश की संस्कृति को और हमारे सामूहिक आत्म सम्मान को दृष्टि में रख कर राष्ट्रपति का वेतन निर्धारित किया था । उन्होंने उस वक्त यह कहा था कि हमारे राष्ट्रपति को यह मिलना चाहिये और राज्यपालों को यह मिलना चाहिये । आज हम यहां बैठ कर यह देखते हैं कि सब को यह सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं, इसलिये, हमारे राष्ट्रपति से यह सुविधाएं छीन ली जाएं । मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे हमारे हृदय की उदारता नहीं बढ़ती । यह हमारा तंग नजरिया है, गलत दृष्टिकोण है । इससे आप जो स्वप्न देख रहे हैं, उसे पूरा करने में आप समर्थ नहीं हो पायेंगे अगर हम इस तरह का निराशावादी, डिस्ट्रक्टिव, सुसाइडल दृष्टिकोण लेकर चलेंगे । अपने राष्ट्रपति का वेतन कम करने के लिये आज कोई राष्ट्र नहीं सोचता । किसी का हमारी तरह से तंग नजरिया नहीं है । कभी आपने सुना है कि अमेरिका ने या जापान ने यह बात कही हो कि हमारे राष्ट्रपति का वेतन कम होना चाहिये । कभी इंगलैंड में आपने सुना? इंगलैंड के अन्दर सोशलिज्म है । वहां से बड़ा सोशलिज्म कहीं नहीं है । वहां पर हैड रानी है, राजा भी होते रहे हैं । वहां पर वेतन के बढ़ने के बारे में तो सुनते रहे हैं लेकिन कभी वहां की संसद् में ऐसी बात नहीं आई है कि वहां की रानी का वेतन कम किया जाए । कभी यह नहीं सुना कि वहां की संसद् यह पास करती जा रही है कि इनका वेतन कम किया जाए क्योंकि उनमें आत्म सम्मान है।

उसको राष्ट्र की प्रतिष्ठा और सुरक्षा

4 P.M. की चिन्ता है, उसको पूरे देश के गौरव

की चिन्ता है । यही कारण है कि इस प्रकार का कोई भी विचार, कोई भी प्रपोजल, कोई भी संकल्प, कोई भी मोशन या कोई भी चर्चा वहां आज तक सुनने को नहीं मिली । इसलिए मैं यादव जी और विरोधी पक्ष के तमाम साथियों से यह कहना चाहूंगा कि इस दिशा में वे सोचना कृपा करके बंद कर दें । अगर आज वह कहें कि प्रत्येक भारतीय को हिन्दी सीखनी चाहिए तो मैं यह कहूंगा कि यह बहुत अच्छी बात कही । अगर वह कहें कि प्रत्येक आदमी को मिनिमम नीड बेस्ड वेजेज मिलने चाहिएं तो मैं कहूंगा कि यह बहुत अच्छी बात कही । सब वर्कर्स को यह मिलना चाहिए, सब

[श्री पी०एन० सुकुल]

को जीने का अधिकार मिलना चाहिए । लेकिन में देखता हूं कि विरोधी पक्ष के तीन वर्षों के शासन काल में किसी ने भी इस प्रश्न को नहीं उठाया । जब मैं देखता हूं कि श्री मोरारजी भाई के शासन काल में केवल एक पार्टी, कांग्रेस (ओ) के तमाम लोगों को गवर्नर एपाइन्ट किया गया तो विरोधी पक्ष के किसी भी आदमी ने इस प्रश्न को नहीं उठाया। जब विरोधी पक्ष के लोग गवर्नर बने तो क्या उन्होंने अपने पैसे कम किये । वे लोग अपने वेतन को स्वयं कम कर सकते थे । हर राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है, हर राज्यपाल ऐसा कर सकता है । यह उसका व्यक्तिगत प्रश्न है । अगर राष्ट्रपति पैसा नहीं लेंगे या एक हजार रुपये लेंगे या दो हजार रुपये लेंगे और अगर ऐसा वे स्वेच्छा से करते हैं तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है । अगर वे लोग खुद स्वेच्छा से बलिदान कर दें, अपना वेतन स्वयं कम कर दें तो हम उसका स्वागत करेंगे । हम चाहते हैं कि अन्दर से इस प्रकार की इच्छा, इस प्रकार की प्रेरणा उद्भूत हो । इन लोगों के वेतन कम करने की आवश्यकता है या नहीं है; यह अनावश्यक प्रश्न है, उस पर जोर देना गलत है । इस प्रश्न के साथ राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा और आत्म-विश्वास जुड़ा हुआ है । वे लोग स्वयं इस विषय पर विचार कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने यादव जी जैसे मित्रों से यह निवेदन करूंगा कि वे कृपया इस प्रश्न पर सोचना बन्द कर दें। एक आदमी का वेतन काट कर कोई बहुत बड़ी बात होने वाली नहीं है । राष्ट्रपति राष्ट्र का शिरमौर होता है। वह हमारे संविधान का मुकुट है। राष्ट्रपति तीनों आर्म्ड फोर्सेज का सुप्रीम कमान्डर है। हमारे देश में राष्ट्रपति क्या नहीं है। राष्ट्रपति के बारे में बैठ कर बनिये की तरह से सोचना या यह कहना कि राष्ट्रपति के ये-ये प्रेरोग्रेटिव्स को काट दिया जाय, उचित नहीं लगता है। मैं तो यह सोचता हूं कि इस प्रकार से सोचना यह बताता है कि हमारा स्टैन्डर्ड क्या है और हमारे संस्कार क्या हैं और हम कितने भारतीय हैं। आप जानते हैं कि भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल से ही डमोक्रसी रही है, यहां पर रिपब्लिक रहे हैं। बिलकुल शुरू के सालों में शायद यहां पर रिपब्लिक न रहे हों, लेकिन बाद के कालों में हमें रिपब्लिक मिलते हैं, एटोक्रटिक शासन मिलते हैं। गुप्त पीरियड जैसे शानदार पीरियड हमारे देश में हुए हैं। अगर आप इतिहास पर दृष्टि डालें तो आपको पता चलेगा कि इतिहास में चाणक्य से लेकर अब तक जितने भी शासन हुए हैं उनमें किसी ने भी यह नहीं कहा कि राजा का वेतन कम कर देना चाहिए या राष्ट्रपति का वेतन कम कर देना चाहिए या उसके प्रेरोगेटिव्स कम कर देने चाहिएं। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की मांग के पीछे कौन-सा सिद्धान्त है, कौन-सी नीति है या इसमें कौन-सी शंकराचार्य की नीति है । Once you fix it, stick to it.

मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि हम राष्ट्रपति के वेतन को कम कर दें या राज्यपाल के वेतन का कम कर दें . . (*Interruptions*).

यादव जी, जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप था। अब मैं बोल रहा हूं, इसलिए आप न बोलें। मैं बहुत अदब से यह बात भी कहना चाहता हूं कि यादव जी ने एक रिमार्क किया कि राज कर्मचारियों को बहुत ज्यादा वेतन मिलता है, वह उनको नहीं मिलना चाहिए। यह संयोग की बात है कि मैं आल इंडिया स्टेट गवर्नमेन्ट्स एम्पलाइज फडरेशन का पिछले 10 वर्षों से चेयरमैन हूं।
Twice I have been unanimously elected.

राज कर्मचारियों के विषय में यादव जी के और विरोधी पक्ष के लोगों के विचार सुन कर सचमुच में मुझे बड़ी लज्जा आई। आप जानते हैं कि राज-कर्मचारी या जो अन्डर-डोग्स कहे जाते हैं, वास्तव में वही लोग शासन को चलाते हैं। हम लोग यहां पर बैठ कर निर्णय ले लेते हैं। लेकिन उन निर्णयों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी, एक्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी इन्हीं कर्मचारियों पर होती है। अगर ऐसा न हो तो हमारा यहां पर निर्णय लेना महज एक ड्रामा हो जाएगा, ढकोसला हो जाएगा। हमने यह देखा है, उत्तर प्रदेश में देखा है, महाराष्ट्र में देखा है, आंध्र प्रदेश में देखा है, केरल में देखा है, वेस्ट बंगाल में देखा है और जहां जहां कर्मचारियों की हड़ताल हुई है वहां देखा है कि कर्मचारियों की हड़ताल होने के बाद कैबिनेट, मंत्रिमंडल बैठ कर निर्णय तो लेता है लेकिन

those decisions are never executed

हमारे यहां श्रीमती सुचेता कृपालानी मुख्य मंत्री थीं, उपसभाध्यक्ष महोदय, 1966 की बात है। हमारा जो स्टेट इम्पलाईज आर्गनाइजेशन, यू० पी० का था, आपने पढ़ा होगा उस वक्त के अखबारों में कि वह हड़ताल 62 दिन तक चली थी,

Was the hartal, for economic demands of white cola employees, it was the longest strike of its kind in the world.

उस समय सब दफ्तर बन्द थे, सचिवालय बन्द था, सब कुछ बंद था। कैबिनेट जो मीट करती थी उसके निर्णय रोज निकलते थे कि इतने हजार लोगों को सस्पेंड कर दिया, इतने हजार लोगों को टरमिनेट कर दिया, इतना वह कर दिया इतना यह कर दिया; लेकिन वे आर्डर अखबारों में आ जाते थे लेकिन was none to type them out, absolutely none to just carry them to the heads of Departments and others, with the result, the papers used to write: The Government has been paralysed. अखबार वाले लिखते थे कि The Government has been paralysed.

उस समय यह हुआ था। तो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनको यादव जी आप किसी तरह भी अपने से भिन्न न समझें। उनका इन्टरेस्ट भी वही है। उनको नीड्स बैस्ड मिनिमम वेज नहीं मिलता, फेयर वेजेज नहीं मिलता। हमारे यादव जी जैसे संसद् में बठने वाले जो गंभीर चिन्तक हैं जो आईन बनाते हैं, कानून बनाते हैं वे अगर इररिस्पांसिबल हो जायेंगे, हाउस में बैठ कर इस तरह की बातें करने लगेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे उन लोगों को निराशा ही होगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसा मैं बता रहा था कि मैं स्वयं आल इंडिया और उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष हूं और मैं ठोस यकीन करता हूं कि गैप कम होना चाहिए मेक्सिमम और मिनिमम के बीच। वहां पे कमीशन बैठ चुका है, गवर्नमेंट आफ इंडिया में नहीं बैठा है लेकिन हमने डिमान्ड की है कि 1 और 5 से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 550 से लेकर 2750 का अनुपात मांगा है। यह इससे ज्यादा हम नहीं चाहते। हम पूरा यकीन करते हैं कि समाजवाद आयेगा परन्तु समाजवाद चिल्लाने से नहीं आयेगा, समाजवाद विडिबिटव होने से नहीं आयेगा, बेन्डेट से नहीं आयेगा और इर-रिसपांसिबल बातें करने से नहीं आयेगा। हमें मालूम है कि जनता पार्टी का शासन यहां हुआ। कौन नहीं था? राजनारायण क्या उसमें नहीं थे, चौधरी साहब क्या उसमें नहीं थे, मोरारजी भाई क्या उसमें नहीं थे † कौन

[श्री पी० एन० सुकुल]

नहीं था ? क्या नहो तीन वर्षों में इन लोगों ने किया ? मारारजो भाई सादिक अली और उस गवनर। का एप्वाइंट किया और वही लाग बठ कर डिमान्ड करते हैं कि कम कर दिया जाय

Either it is a big joke or it is gome-thing whch must be ignored totally. It needs no consideration. 1 am sorry to say to my esteemed leader, who has been here for such a long time— I am a newcomer, I) am not even a month old in this august House—that Bhupeshda should not have brought in this Bill here. '

It is apparent that he is not interested in the decision itself and when he knows "that it cannot be done, it is all the more funny that he has brought forward this type of motion before this august House,

मैं इसलिये इस सदन के सदस्य आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं जेल में था, मैं पांच वर्ष जेल में रहा हूं, इस सदन में बैठने वाले कितने सदस्य हैं जो पांच साल जेल में रहे हैं

just for small matters like D.A. this demand or that of the State employees and others.

इमरजेंसी में बन्द रहा हूं बड़े नजदीक से मैंने देखा है।

When J. P, came to Lucknow in August 1974 I was the convener of that meeting. Ii welcomed him,I conducted that meeting; not that I did not feel like that.

लेकिन आज जब हम उन्हीं लोगों को, उन्हीं पार्टियों के उन्हीं नेताओं को देखते हैं तो पाते हैं वे केवल एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। यह सिर्फ इसलिए हम कहें कि राष्ट्रपति का वेतन कम किया जाए क्योंकि राष्ट्रपति हमारी पार्टी का नहीं है वह किसी और पार्टी का है यह गंदा नजरिया है। हमें राष्ट्रपति के साथ, राज्यपाल के साथ जो हमारे कांस्टीटयूशन में प्रोवाइडेड हैं जो हमारे पोलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी प्रतिष्ठा के साथ खेलना नहीं चाहिए। यह समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रपति का अगर सम्मान चला जाए तो भूपेश जी का सम्मान चला गया, पी० एन० सुकुल का सम्मान चला गया।

Once he is Rashtrapati, he has been elected Rashtrapati,

संविधान में जो कुछ है वह पहले से ही है। आपने उस कांस्टीट्यूशन को पास नहीं किया यह एक जेनरेशन पहले पास हुआ। उस समय हमारे महान नेता पंडित जवाहरलाल नेहरु और डा० राजेन्द्र प्रसाद जी थे। उन समय में संविधान पास किया गया। कृपा कर के अब उसका पोस्ट-मार्टम न कीजिए। मैं तो समझता हूं कि तब से लेकर आज तक जितना प्राइस इनक्रीज हुआ है हमारे राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाना चाहिए-अगर हम बढ़ा सकें। हमारे राज्यपाल का भी बढ़ना चाहिए। तब हम देखेंगे कि हमारे राष्ट्रपति और राज्यपालों का आचरण कितना शुद्ध है; जो आचरण आज हमें खराब लगता है। अगर हम उनकी सुविधाएं बढ़ाते है तो उनके आचरण में फर्क आ जाएगा। मुझे उत्तर प्रदेश के तमाम राज्यपालों के बारे में मालूम है। मैंने सचिवालय में बैठ कर देखा है। मैं आपके द्वारा इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि ऐसे राज्यपाल वहां रहे हैं जो कि पेड़ों पर लगे हुए आमों को भी गिना करते थे। उनको यह पता होता था कि किस पेड़ में कितने आम लगे हैं। अगर उसके अन्दर रहने वाला कोई छोटा कर्मचारी या उसका बच्चा जाकर आम तोड़ लेता था तो इसके लिए सवाल करते थे। ऐसे राज्यपालों को मैं जानता हूं। जो सरकारी खर्च पर पूरी पोशाक तयार करते थे और अयोध्या जाकर दान भी सरकारी खर्च में से करते थे। ऐसे राज्यपालों को अपना आचरण बदलना चाहिए। लेकिन यह तभी होगा जब

हम उनको किसी प्रकार का अभाव महसूस नहीं होने देंगे। उनकी प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने देंगे।

SHRI BHUPESH GUPTA: One thing I may tell you, I introduced this Bill in 1977—during the Janata rule.

श्री पी० एन० सुकुल : भूपेश जी मैंने आपसे कहा कि मैं आपको राजनीति में पहले ही अपना पूर्वज मान चुका हूं। लेकिन यहां पर व्यक्ति का प्रश्न नहीं है। यहां पर पूरे सदन का प्रश्न है पार्टी का प्रश्न है। हम अपना छोटापन क्यों जाहिर करें। क्या हम अपने छोटेपन को कटेन नहीं कर सकते। यह हमारी एक तरह से निराशा व्याप्त हो रही है, क्या हम इसको कम नहीं कर सकते। क्या हम अपने राष्ट्रपति को अपने राज्यपालों को गौरव प्रदान नहीं कर सकते। आज जरूरत इस बात की है। मैं आपको बता रहा था कि एक जमाने में उत्तर प्रदेश में करीब 150 कर्मचारी चौधरी साहब की सरकार ने विक्टेमाइज किया था। We remained victimised for four years. We were reinstead by the Government of Pt. Kamlapati Tripathi in 1971. उन चार वर्षों में जब हमने देखा कि चौधरी साहब आए, गुप्ता जी आए, टी० एन० सिंह आए लेकिन हम लोग चलते रहे, मिलते रहे, हमको न्याय नहीं मिला। तब सन् 1969 में असेम्बली का इलेक्शन हुआ तब आपने सुना होगा कि एक पार्टी बना ली गई थी जिसका नाम मजदूर परिषद् था उसमें टीचर्स, डाक्टर्स, वकील वर्ग के लोग थे। यह एक प्रकार का एक लेबर पार्टी की तरह से एक्सपेरीमेंट किया गया था। Although that party had no money, had no funds, t till इसके लिए 100 कैंडीडेट्स फील्ड किए गए थे। इसकी वजह से इलेक्शन में भारतीय क्रान्ति दल को बड़ा फायदा मिला था; क्योंकि कांग्रेस के वोट कट गए थे। उस जमाने में मजदूर परिषद् का चुनाव मेनीफेस्टो निकाला। I was the General Secretary of that party. उसमें हमने यह डिमांड की थी कि राज्यपाल का पद समाप्त होना चाहिए; क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक स्पीकर जो है वह बैठा हुआ है उसके साथ दो डिप्टी स्पीकर हो सकते हैं। स्पीकर राज्यपाल का यह काम देख सकते हैं; क्योंकि राज्यपाल को टेक्निकली दस्तखत ही करने पड़ते हैं। That the Speaker can do. We can entirely dispense with the entire paraphernalia available to Rajyapals. यह हमारी उस समय फीलिंग थी। कांग्रेसी शासन आया, विरोधी शासन आया, सब आए लेकिन किसी ने अपने समय में कोई इसकी चिंता नहीं की, इसको कम करने की बात नहीं सोची। मैंने सोचा शायद इसको कम करने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए हमारा देश यह नहीं सोच रहा है। इसलिए शायद मैने सोचा कि राष्ट्रपति की जो तनख्वाह है या दूसरी जो चीजें हैं ये ठीक हैं, उचित हैं। मैं सदन के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि हम इस प्रस्ताव को जो भूपेश गुप्त जी लाये हैं, बहुमत से डिफीट करें, इसको गिरायें। अगर प्रस्ताव पास कर सकें तो ऐसा करें कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के गौरव में कोई अभिवृद्धि करें, उसको कम करने का हमें कोई अधिकार नहीं है या यह कोई इस तरह का फण्डामेंटल राइट नहीं है जिसके ऊपर हम यहां बैठ कर चर्चा करें। फण्डामेंटल राइट भी आपने देखा कि हमको कितने प्राप्त हैं, कितने हैं, कैसे हैं, हम नहीं कह सकते हैं कि हम किस स्टेज पर हैं। अभी तो हम रिजोल्यूशन की स्टेज में हैं। अभी तक हम बहुत पीछे और हमें एक्सट्रीम पर तो जाना नहीं है, यह हम सीख चुके हैं। इसे चाहे हम नक्सलवादी

[श्री पी० एन० सुकुल]

विचारधारा से सीख चुके हों चाहे किसी और विचारधारा से सीख चुके हों । लेकिन आज पूरा राष्ट्र यह महसूस करता है कि इंदिरा जी का जो शासन आया हैं दुबारा वह सिर्फ इसलिए आया है कि देशवासी यह महसूस करते हैं कि आपोजीशन पार्टीज आयीं और चली गयीं पर उन्होंने कुछ किया नहीं । कोई भी रिलीफ वे हमको नहीं दे पाये हैं। आपसे मैं पूछ सकता हूं कि इन तीन सालों के जनता शासन में टाटा और बिड़ला की आमदनी में कितनी कमी आयी है । कहा जाता है कि टाटा और बिड़ला को कांग्रेस के लोग उठा रहे हैं । मैं जार्ज फर्नेन्डीज साहब को जानता हूं, तमाम लोग हमारे व्यक्तिगत मित्र रहे हैं। उनके बोनस के प्रश्न पर मैंने एड्रेस किया है। 74 में जब मैं पी० ए० सी० के आंदोलन की वजह से एक साल जेल में था

Twice I went to the jail and he proposed that I contest on his party ticket, but I refused.

बड़ा आदर मिलता था । लेकिन हमें पता चला कि बड़े-बड़े समाजवादी नेता यहां पर आकर सरकार में बैठ कर बिल्कुल बदल गये हैं । एक आदमी कानून के मुताबिक 10 हजार या पाँच हजार रुपया लेता है तो क्या बुरा करता है; पर तुम यहां बैठ कर गैर-कानूनी ढंग से लाखों करोड़ो आमास कर सकते हो; तुम्हारी आत्मा को कष्ट नहीं होता है? अब ये राजनीतिक नेता हैं और खास करके विरोधी पक्ष के उत्तर प्रदेश में मैंने खास कर बहुत देखा । उत्तर प्रदेश में तो अभी तीन साल से था मैंने आपको बताया कि मैं बन्द था इमरजेंसी में और उसके बाद ही रि-इन्स्टेट हुआ और तीन साल वहां रहा ।

I was a Gazetted Officer in the UP Secretariat. Now I am retired, of course.

मैं वहां रहा और वहां मैंने देखा कि दो दो सौ, चार-चार और पाँच-पाँच सौ रुपये लेकर जनता पार्टी का मिनिस्टर ट्रांसफर कर रहा है । दो सौ रुपये लेकर ? मैंने उनके नाम बताये, मैंने कहा कि क्या इसलिए इमरजेंसी में बन्द रहे थे. . . (*Interruptions*)

एक माननीय सदस्य : दाम की बात नहीं है ।

श्री पी० एन० सुकुल : दाम की बात नहीं है, आप शिफ्ट मत कीजिए । दाम गिराने की बात आप करते हैं, परसों मन्डे को जब मैं इन्फारमेशन और ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री पर बोलूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि दाम गिराने का क्या है, कितने दाम गिराये, जनता सरकार का बजट कैसा था, हमारी सरकार का बजट कैसा है । चौधरी साहब जो बजट लाये थे वह कैसा था और उससे कितना इन्फ्लेशन हुआ, कितना मनी सप्लाई एक्सपेंशन हुआ

Do you know, Galloping. Now every-one knows, Perhaps we are be-having most mechanically.

बहस होनी चाहिए, एक रिजोल्यूशन आना चाहिए । पास हो या न हो, ठीक हो या न हो, गलत हो या न हो

And unless we are going to behave like that, we are not going even an inch farther, I tell you.

इसलिए मैं अपने तमाम सदस्यों से उपसभाध्यक्ष के माध्यम से यह दरख्वास्त करूंगा कि अगर हमको एक बच्चा राष्ट्र ईमानदारी से बनाना है तो हमें अपने नजरिये को बदलना होगा, थोड़ा करीब आना होगा, समझना होगा, को-एग्जिस्टेंस और को-आरडीनेशन की भावना लानी होगी । अगर हम यह भावना नहीं लाते हैं तो जैसा कि हमारे यादव जी कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार जो थी वह इन्द्र थी वह गलत काम कर रही थी, जनता सरकार

आयी तो वह नहुष बन गयी, वह आकर इसी तरह के काम करने लगी, इसको भी गिराया गया। बिल्कुल सही बात है। पर इन्द्र जो है वह तो ठीक हो भी सकता है लेकिन नहुष को कोई ठीक नहीं कर सकेगा। मैं चाहूंगा कि हम नहुष न बने, इन्द्र बन कर अपने को सुधारने की कोशिश करें। आज हमारे राष्ट्रपति किसी इन्द्र से कम नहीं हैं। आज इनका नाम राष्ट्रपति है, आप इनका नाम इन्द्र भी रख सकते हैं, आप उन्हें कह सकते हैं 'राष्ट्रेन्द्र' राष्ट्र का इन्द्र है। आप उनको क्या नाम देते हैं क्या नहीं, यह तो डिपेंड करता है आपके संस्कार पर, आपकी परम्पराओं पर, आपकी शिक्षा और जैसे ब्यूज होंगे उस पर, आपके चरित्र पर। आप समझते हैं कि जो आपकी जनता सरकार नहीं कर पायी वह कांग्रेस नहीं करती है या नहीं कर पायी है। हम चाहते हैं कि वह करे। लेकिन वह जो सरकार है या पार्टी के लोग हैं या दूसरे लोग हैं, विद्वान हैं, वे इसको उचित समझते हैं, इसलिए नहीं करते हैं। तो क्या कारण है, सबसे बड़ा कारण हमारा राष्ट्रीय चरित्र है, चाहे इधर बैठने वाले हों या उधर बैठने वाले हों। श्रीमन्, मैं एक साल 1973–74 बन्द रहा था, जैसा कि मैंने कहा पुलिस के आंदोलन के सिलसिले में। मुझे बन्द करने वाला कौन था। आपको बताऊं, तो आप हंसेंगे, श्री के० सी० पंत। हमारी स्टेटमेंट थी कि ज्यादती नहीं की जाए। उन्होंने कहा कि पकड़ लो और साल भर के लिए बन्द कर दिया गया। पहले चौधरी साहब ने सब से पहले 1966 में मुझे बन्द किया और बाद में जब इमरजेंसी आ गई, कोई आंदोलन कर्मचारियों का नहीं था, लेकिन बन्द कर दिया गया और आज बहुगुणा जी कोई भी इस पार्टी में नहीं हैं।

आज यह कुछ पार्टी के लोगों के सोचने का जो तरीका है, यदि उस तरीके को नहीं बदलते तो मैं आप को बता दूं कि न तो हमारा देश उन्नति करेगा, भाषण चाहे हम जितने लम्बे-चौड़े दे दें, यदि हम प्रैक्टिकल नहीं होते और जो असलियत है उसको नहीं देखते ....It is alwayse that the middle path is the best path. लड़ेंगे नहीं, यथा सम्भव थोड़ासा एडजस्ट करके इसको बदलना पड़ेगा। भारतवर्ष इतना विशाल देश है और यहां 70 प्रतिशत इलीट्रेसी है। यहां कोई अपने अधिकार को नहीं समझता, कानून को नहीं समझता, कांस्टीच्यूशन नहीं समझता और आप बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के वेतन की। 99.9 प्रतिशत लोगों को मालूम नहीं होगा कि What are the wages of our Rashtra- pati or of the Rajpal या तो आप आकर उनको बता दें कि राष्ट्रपति का वेतन कम होना चाहिए। क्या कभी आपसे किसी ने गांव में सवाल किया है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति का वेतन कम होना चाहिए ? ऐसा नहीं है कि जन-भावना है। लेकिन हम इसकी डिमांड करते हैं only because we belong to a particular party, we are either on this side or that side. मैं चाहता हूं कि हमारे विरोधी दल अगर केवल साल भर के लिए —It is my appeal to them through this House. उन्होंने देख लिया है कि बड़े-बड़े नेता हार गये। आज श्रीमती इन्दिरा गांधी से कोई भी बड़ा राजनीतिक नेता इस देश में नहीं है। इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। पूरे हिन्दुस्तान ने ओपीनियन दी है। हम कुछ भी कहते रहें, हमारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। She is the most acclaimed leader of this country perhaps the only leader. अगर हम ऐसे लीडर को पाकर के भी आगे नहीं बढ़ना चाहते, हमारी तमाम प्रैक्टिकल डिफीकल्टीज एनर्जी, पैट्रोलियम, कोयले के क्राइसेस को यदि साल्व करने में अपनी सरकार की मदद नहीं करते और उनकी चादर पकड़ कर तानेंगे तो यह कांस्ट्रक्टिव काम नहीं है। मैं तो कहूंगा कि एक साल तक कोई विरोध इस सरकार का नहीं करेंगे, टोटल स्पोर्ट इस सरकार को देंगे और इन दो सालों के अन्दर यदि हमारा आशय पूरा नहीं

[श्री पी० एन० सुकुल]

होता यह मिनिमम डिमांड्स हैं और यदि पूरा नहीं होता तो दो साल के बाद सब कुछ करेंगे जो हमें करनी चाहिए और मैं तो आपका साथ करूंगा, अगर यह सरकार काम नहीं करेगी, तो दो साल के बाद आकर विरोध में बैठूंगा। लेकिन जबरदस्ती के लिए लड़ना, झगड़ना शोभा नहीं देता। प्रैक्टिकल काम करें, भावना लेकर चलें, चेतना लेकर चलें, स्पंदन लेकर चलिए, बुकिश मत बनिये। मार्क्स ने भी कहा है कि कम्यूनिज्म जहां-जहां आता है, तो क्लाइमेट के मुताबिक आएगा, वहां के रहन-सहन कंडिशंस के मुताबिक आएगा, जरूरी नहीं कि एक पैटर्न पर आएगा। समाजवाद आएगा तो एक पैटर्न पर सारी दुनिया में आएगा, यह जरूरी नहीं है। हमारे यहां तमाम जब गणराज्य थे, उस समय भी था। लेकिन इस तरह की कोई प्राबलम नहीं थी। रामराज को हंस करके उड़ा देते हैं। लेकिन राम के जैसा राजा मिले तो क्या कोई इनकार करेगा या यह कहेगा कि राजा राम चन्द्र को मुकुट नहीं पहनना चाहिए। इसी लिए जो हमारे साथी कहते हैं कि हमारे राष्ट्रपति को जो मिल रहा है, वह नहीं मिलना चाहिए। मुझे हंसी आती है और अपने देश के दुर्भाग्य पर रोना भी आता है। मैं दख्वास्त करूंगा कि हमारी इस अगस्त असैम्बली में जो बैठने वाले साथी हैं—भूपेश गुप्त तो इसे दुबारा लाए हैं, एक बार पहले ला चुके हैं, पर बुरी तरह से डिफीट हुआ है? समाप्त

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: *Hon. Mr. ViceChairman, Sir, Shri Bhupesh Gupta has brought forward this Bill in the House to amend the Constitution. I fully support this Bill. But before going into the subject-matter of the Bill, I would like to say a few words in English about the Private Members Bill.

want to speak a few words in English. It seems that we are not serious about Private Members Bill*. I enquired and found that from 1978 the Private Members Bills introduced here are still pending for passage. We take them one by one and pass the whole day on one single Private Member's Bill. So, everything gets stuck up for two years for a Private Member's Bill to be passed. That does not show our seriousness. Instead of getting the whole day for one bill we should have quickly discussed the pending Bills so that the present Bills could come quickly for passage.

I have given notice and I have aready moved for amendment of the Citizenship Act, Sir, you will be surprised to know that the refugees who are here, strictly according to the law, the Constitution and the Citizenship Act and its present interpretation, are not citizens of India. That means three-fourth of the population of my State, almost 98 per cent of the population of Tripura and the neighbouring States will go without having any Indian citizenship. So, I introduced that Citizenship (Aemendment) Bill so that the Government can modify the citizenship Act, 1955. I should have expected that this Bill without being taken up after two-and-a-half years, should have been taken up immediately so that we could have helped the refugees.

•Vice-Chairman, Sir, there are three aspects of the subj'ect-matter which we are going to discuss today. We have accepted the concept of socialism According to the concept there should not be wide gap between low income groups and high income groups. The sonner that gap i_s narrowed down, the faster we move towards socialism. But unfortunately we do not practise what we

preach. That is why we do not bother about how much salary and allowances the President and the Governors are getting So the Bill of Shri Bhupesh Gupta should be considered seriously and a decision taken thereon. I feel that when we as representatives of the people talk of poverty in our country in this House, we are never taken seriously by those people who work in the field and suffer poverty in life. They know that we have paid them lip-sympathy only. So the credibility gap comes in and as such there is a crisis of confidence between us. If we could make them feel that we are conscious of their poverty, we could have earned their confidence.

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : हमसे रजा । सुन रहे हैं ?

श्रीमती पूरबी मुखोपाध्याय : सब लैंग्वेज में बोल सकते हैं । कोई हिन्दी बोलते हैं, मैंने सोचा बंगला में बोलूं ।

*When our Constitution was adopted, ours was a newly independent country. At that time we did not have administrative experience. So we did not have a clear concept as to what system of Government we shall adopt. So in our enthusiasm we adopted a system which we sought to modify later on. The institution of Governorship was actually introduced by the Britishers. We thus put old wine in a new bottle Today it requires rethinking whether we should retain the institution of Governorship or not. I am not saying this thing since I belong to the Opposition Party. I would have said the same thing if I had sat in the Treasury Benches. It is not proper that a mistake, once committed, should never be rectified. That should never be our logic. We should never feel shy to modify the institution of Governorship in its present form as there is today a strong demand to that effect.

If we had made some mistake, we should own it. It should be modified, we should not feel shy to modify it.

What is the real picture today? **How far is the institution of Governorship relevant in the present day? Directly or indirectly, the Governors come to know about the feelings of the Central leaders as to what sort of administration or what sort of party they want in the State legislature. At the back of their minds, they have a political thinking. They cannot dissociate themselves from their inner political prejudices, political bias, and they cannot act in the way the Constitution expects them to act. Neutrality is a very difficult thing for a person who does not attain that level of mental thinking. So what happens in the process? Only in case of emergency, in case of war, the Governors can act also as the local representative of the Central Government with powers over the Navy, over the Army, over the Air Force, as the President's nominees at the local spot.

Cannot the Constitution evolve some method by which this can be avoided? There should be rethinking on this today. We do not want it to be done today. But my suggestion is that the thinking process should start not only on one item but on all the articles of the Constitution. How far was it valid in 1950 and how far is it valid now in the present circumstances, because the Society is moving forward. Sometimes while moving forward, it also goes back. And in the process, our values have changed. In the process our mental thinking also gets changed. If this system of defections is not stopped and stopped for ever through legislation, no Government will ever be a stable Government.

---

*English translation of the original speech in Bengali.

**English speech.

[Shrimati Purabi Mukhopadhyay]

Janata Party came to power with three-fourth majority. They were enjoying three-fourths majority. Why could they not come back in the next elections? Because when the people elected their representatives, they had certain expectations, certain dreams. They thought well, if the other party could not fulfil our expectations let us see whether this party can. When they found that instead of fulfilling their expectations the Janata Party could not even stand as a homogeneous body, when they found that they were fighting each other and were vindictive instead of being democratic, people got fed up. Today you say that Janata Government did this, they did that. That is why they were sent back. Do you want to follow their examples and their failures? Certainly not. If you do the same thing, people today or tomorrow will find out your intentions. It is too early for them to assess now.

Today the price of sugar has gone up and it is being sold at Rs. 7/- a k.g. in the retail market. Do you think people can afford to purchase it? Either you increase the quantum of sugar distributed through the fail-price shops, or make it available to the people at a reasonable price. Otherwise, people will get fed up with you also. Their interest is only in getting it at a reasonable price.

There is a gap between the common people and others like us whose average income, as Members of Parliament,, is not less than Rs. 1,500/-per month. If we cannot afford, as a j Members of Parliament, to purchase sugar at Rs. 7/- or Rs. 7.25 or Rs. 7 50 —tomorrow it may be Rs. 8/- do you j think a common man, a labourer or a peasant or an unemployed person who has to maintain a family, can afford to buy it? Same is the case with vegetables. We in Bengal are j ish-eaters. We are not fond of vegetables. We call it 'ghas patha'. **I** cooto my food. If you come to Calcutta;, you will see me in the kitchen and I do not have a helping hand. That has been my life throughout. Therefore, I know where the shoe pinches. I can imagine the plight of the poor people who are not Members of Parliament because never in my life I have lived in a different way. I was either in the student and youth movement or in the women's movement. I have never had to choose * profession. I always felt dedicated to this country. I did not have any other kind of life. There is nothing for me to fall back upon. I do not have any other income. Of course I am a wife-of a Professor who has some income with which he can maintain a family. Our principle is: Do not go beyond your means, whether you are a political worker or social worker or anybody else. We should not misuse our power for our own benefit. That, should be our philosophy. And I have accepted that philosophy and I have adopted it. I have never cared for the chair. I believe in that philosophy which Gandhiji showed us and which he implemented in his life. Much of the corruption in public life would have disappeared if we were above corruption. That is by the way. So, there is a gap between one income group and another income group.

People round about us speak o[1] u* as big leaders. That creates in us an inflated ego about ourselves, though we know we are nobody. Tomorrow when we go to the people they will simply turn their face, if we do not fulfil their expectations.

So, we are lost in public life. Then, why the question of defection comes? Is it a selfless effort? Do you think that the people feel that by my changing sides and going to the other side people are going to be benefited? Sometimes it is a lucrative post; some times it is money; and sometimes it is the influence of *dadas* and *didis* who are causes of defection. Meanwhile, the people get frustrated

with us and when the defection takes place, it always t ikes place because the party encourages defection with an eye on the *gad Ihi,* with a view to getting into powej and, there, Sir, the Governor has to play a very big role. In his own a ;sessment he has to see and according to the Constitu tion, it is the report of the Governor which matters. know of States where—I am not saying anything about the present or the past—the Chief Ministers tost their majority, but the Governorf did not send their reports Why? it is because the Governor feels that h;;re is a man as the Chief Minister who is supported, who is wanted, and who is liked by the Central leadership and so, he should not bg a'lowed to fall. What for our Constitution has made the institution of Governorship? Is it for this purpose? There are Chief Ministers who have their majority and who have not lost their majority; but the Governors send repoi ts saying that these men should be changed. Only in the case of a constitutional break-down when a State Government cannot function constiti tionally with the authority that hu ? been vested in it through the Const tution, can the Chief Minister be dismissed and the Governor is the greatest judge of the situation. So, if we have Governors who can really judge the issue irrespective of their party affiliations or their past life hefore they became Governors, then their recommendations will be justified. Otherwise making a wrong judgment wi\\ make the Goven ment ridiculous because on the basis of that judgment, of that assessment, of that Governor the Ministry w 11 be unjustifiably dismissed. That i:. why demands come about the Centre-State relationship, about the federal structure of our country and oui Constitution, about the unitary syste n and the defects or merits of the unitary system. Let us judge it by ano'her yardstick. If we think that the people are supreme, if we really belie*-e in that, then no defection should be allowed, because the people have elected them and no Governor shoul 1 be encouraged to engineer any defectio - If you can stop that, this country can be saved.

Now, coming to the expenses in the case of the President and the Governors, if we take the yardstick cf the world, in relation to the per capita income of the country concerned, the salaries of the Cabinet Ministers are fixed and they are fixed with that yardstick. So, when we hear people say, "Oh, in the British Parliament they get so much as MPs", or ! "Oh, the members of the American Congress get so much or the members of the Senate get so much", we do not compare the per capita income of that country and the gap between the highest income group and the lowest income group. That is why we end up in error. If we feel that we have to do justice to the post in India, we must remember that India has never in its conception and in its philosophy decided anything on the basis of the wealth of a person or judged a post by the salary or the pay it carries alongwith it. Take the case of the teachers. Until yesterday, they were the lowest paid. My husband entered as a lecturer in a college on Rs. 135/. as his salary. I entered as a school teacheress, as Headmistress and got Rs. 60/- per month; a primary school teacher got Rs. 5/-. Why are they not the highest paid? Gandhiji said; A cobbler should get as much as a barrister gets in this country. And we quote Gandhiji. He said: I will feel guitly even to take a morsel of food till my people get at least a morsel of food themselves. We attend dinners and lunches given by big businessmen. Do we remember that they get this wealth by exploiting the people, and it is that wealth which is feeding us? No. It is a double standard. That is why there is the crisis of confidence. What we say, what we preach, we do not follow ourselves, but we expect the people to follow. This is ridiculous.

Somebody said that the Rashtra-pati Bhavan should be used as a hospital, sir. ours is a free country, and under the leadership of Shrimati

[Shrimati Purabi Mukhopadhyay]

Indira Gandhi, who is accepted all over as one of the greatest leaders of the world, we will have foreign dignitaries visiting our country. When I say this some may be surprised that Purabi Mukherjee, sitting in the Opposition, is saying this. I visited some countries in connection with some conferences. Every leader and members of his delegation told me about the respect and regard they have for Mrs. Gandhi. It is nothing new. We have our differences inside the country. When we go out, we go as Indians; we do not go there representing this party or that party. Whatever grievances we have, we do not air them outside. I was very happy when they told me about her. I do not know whether Mrs. Gandhi knows it or not— the unique position she has at least in our friendly countries in the non-aligned nations, and also in other places. Some may not like her to be as powerful as we want her to be, in some countries because of their vested interests. If you read between the lines the speeches of the American Congress Members in their Committee meetings, where they spoke about supplies of enriched uranium for our Tarapore station, you will see that they said; we shall have to reconsider our position *vis-a-vis* India; they said that Mrs. Gandhi is a powerful Prime Minister and let us not take a hostile attitude towards India. This is our status in the international world. We would expect foreign dignitaries to come and visit this country, meet our leaders and meet our Prime Minister. You have some difficulties about keeping them in some big hotels and keeping them in other places which their position demands. You use the Rashtrapati Bhavan for that. If you make it into a hospital, well and good. But one cannot be delinked from the other. If you make it a hospital for special treatment for VIPs, this we will be refusing to accept. You make it a Guest House for the visiting dignitaries. Make it a Guest House for research students and scholars who come to our country, and utilise that building. It is too late now to say... (*Interruptions*) Sir, it is fantastic for any Rashtrapti of a country like India where 83 per cent of the people still live below the subsistence line and where 90 per cent people are poor. जिस समय मेरा टाइम हो जाए आप मुझे बता दें। This is a non-official day and there is no time limit.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): This time-limit has been removed for today.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: So in a place like India where so much abject poverty is still there, for this country's Rashtrapati to live in that big palace is something fantastic, something which should have been remedied long back and it is never too late. When Rashtrapati said that he wanted to live in a smaller house, we believed him because he comes from the rural area and he has cultivated himself that way. But these Governors are sometimes making fuss about the small cottage they want to stay in. But in that small cottage they want all the comforts. Please remain in the Governor's house because these are the legacies we have received and we did not have to spend money for building. But to make small cottages as comfortable as they expect them to be will be costly. May I ask what were they doing before they became Governors and what were the kind of houses they were living in? Also, what are the people who are being appointed as Governors that they should expect luxury at the cost of this country's exchequer? Even if they come from wealthy families, let them add themselves. We have M.P.s accommodation which is quite reasonable at a minimum rent. If an M.P. wants some changes, some money is spent. Consequently, the rent of all the M.P.s occupying that house subsequently gets increased because of the luxury of the other M.P. his predecessor, living in that house. Why should we do that? If an M.P.

is not satisfied wit: i the present housing system, let hin or her spend from the pocket. This legacy should not be left for hi_s or he successor in that house. Till we arc able to raise the standard of the co nmon people, how does our Governoi ask for additions and alterations vhich cost money from the State Exchequer? We are not supposed to discuss about the establishment of the Governor because that is the convention. We do not discuss the co?t of the establishment, their arrangements and all that. That is why they should exercise restraint on their household affairs. But they don't. Nor should we discuss it. But today is the non-official day and some people don't remember that there is a convention and that there is a rule that we do not discuss the establishment of the Governors in the louse, and we are discussing it today

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANE: H KULKARNI): Madam, I request *you...*

SHRIMATI PURABI MUKHO-PADHYAY; I am Bnishing. I remember that there i_s an Half-an-Hour Discussion at 5.00 jvr.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANEJ-H KULKARNI): You may apply the brake now so that you may be able to finish by 5.00 P.M.

SHRIMATI PL RABI MUKHO-PADHYAY: You night have noticed, Sir, I started my motor car with a brake.

THE VICE-CH A.IRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Keep it in the se ond gear.

SHRIMATI PURABI MUKHO-PADHYAY; Anyway, my speech is not out of control, Sir

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI) It is completely under control.

SHRIMATI PURABI MUKHO-PADHYAY: There may be an emergency stop also.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): But I am very safe here.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: Sir, this demand would not have come if the disparity was not so glaring. We do not have an income and wage policy. There is no ceiling on incomes though there is a ceiling on wages. Though there is a ceiling on expenditure, actually it is not being followed. There is no proper policy where the income is linked with wages. So, what happens? When we feel that it should be sanctioned, we do it out of turn without considering that a time has already come when we should reconsider the whole thing, that We will be lavish in paying a salary of Rs. 10,000 to the Rashtrapati and Rs. 5,000 to the Governors, plus the perquisites. . This is the solid amount that they get in their hands. Ultimately, $_G$f course, after the Defection Bill is passed, after a rethinking on the whole process | about the institution of Governorship, we may have to do av/ay with the whole thing. Till it is done away with, at least, reduce it to the extent as has been suggested by Shri Bhupesh Gupta. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Now, I will call the next speaker Shri Bagaitkar, please.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY; Sir, one more thing. As I said in the beginning, the non-official Bills should be disposed of quickly so that the list can be completed. There are some important Bills, specially the Citizenship (Amendment) Bill. It is not that 1 brought that Bill, but they are important Bills and they should be disposed of quickly.

The Vice-Chairman (Shri R. R. Morarka) in the Chair]

श्री सदाशिव बागाइतकर (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जो बिल सदन के सामने श्री भूपेश जी ने रखा है उस का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस बिल के बारे में जो विचार रखे गए है उसमें बुनियादी सवाल यह है कि हम राष्ट्र के निर्माण में किस मूल दृष्टि से विचार करते हैं और किस पर फेथ रखते हैं। कुछ मित्रों ने इस पर जो भाषण किए उनके भाषण सुनने से मेरे ऊपर यह प्रभाव पड़ा कि आजादी की लड़ाई में जो सबक हम लोगों ने सीखा, जो प्रेरणा हम लोगों को मिली शायद उसी को या तो यह जानते नहीं हैं या उसको घुमाना चाहते हैं। कुछ लोगों की हालत यह हो सकती है कि अब सारा इतिहास वह चीज बन चुकी है और ऐसे चंगेज खान, बाबर या औरंगजेब हों वैसे ही इन चीजों में से इतिहास का पढ़ना है। यह इसका भ्रम हो सकता है।
5 P.M. लेकिन मैं मानता हूं कि राष्ट्र के निर्माण मे जिस विचारधारा को हम लोगोंने माना है उस विचारधारा पर अमल कैसे किया जाये ; यह चीज उससे जुड़ी हुई है। मुझे आश्चर्य है और अफसोस है इस बात का कि ऐसे मामलों पर सोचते हुए भी हम लोग आज जिस किसी कारण से जिस किसी दल में बैठे हुए हैं, उसको भूल भी सकते हैं। किसने क्या गलती की है उसका बखान . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R MORARKA): Mr. Bagaitkar, you could kindly continue your speech on the next occasion It 19 now 5 o'clock and we have to take up the half-an-hour discussion. Yes, Dr. Bhai Mahayir.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION ON POINTS ARISING OUT OF ANSWER TO STARRED QUESTION 1 G VEN ON 23RD JULY 1980 REGARDING SUGAR PRICE DETERMINATION ORDER, 1979-80.

The Vice-Chairman (Shri Dinesh Goswami) in the Chair]

DR. BHAI MAHAVIR (Madhya Pradesh); Sir, I beg to raise a discussion on points arising out of Starred Question No. 1, replied on the 23rd July, 1980.

Mr. Vice-Chairman, Sir, towards the close of the last session we had an opportunity to discuss sugar, but that was the sugar that was imported, and the Minister who replied to the discussion, therefore, was the hon. Minister of Commerce. Today we are again discussing sugar, but it is not the import of sugar. It is s[u]8[ar] poHcy in general, sugar distribution, sugar prices, etc., and we have the hon. Minister of Agriculture here to reply to the discussion.

This is a fact, Sir, that this sugar has two Ministries to deal with it, perhaps more than two, but for our present purpose we have two, and these two Ministries have gone through an episode which was very interesting for a number of reasons. On the question of imports itself, Sir, the country knows that there was a wrangle, and it is not known whether the Agriculture Ministry approved of the imports or it did not There were reports that the Agriculture Minister was taken totally by surprise when the decision to import it had already been taken and probably the contract